- 17th Year
- Issue: 320
- 10.04.2024 (WEDNESDAY)
- ROURKELA
- R.N.I. No. ORIHIN/2006/18978
- (Pages-6)
- Price:2.00

e-paper-www.thekalingasamachar.com

दैनिक

कलिंग समाचार

The kalingasamachar

प्रकाशक एवं संपादक : प्रकाश कुमार धल

Published From Rourkela

अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तारी से नहीं मिली राहत

नयी दिल्ली ०९/०४ (संवाददाता): कथित दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय ;ईडीद्ध द्वारा उनकी गिर तारी को चुनौती देने वाली मु यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर दिल्ली उच्च न्यायालय आज अपना फैसला सुनाया। दिल्ली उच्च न्यायालय ने मु यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ईडी द्वारा उनकी गिरफ्तारी और उन्हें ईडी रिमांड पर भेजने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी। जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने जिन लोगों के बयान पर कहा जा रहा है उनके बयान कोर्ट की निगरानी में रिकॉर्ड कराए गए थे। लिहाजा इनकी अहमियत है। राघव मगुंटा या शरत रेड्डी हो सभी के बयान ईडी की मौजूदगी में मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज कराए गए थे। कोर्ट ने कहा कि दस्तावेज के मुताबिक केजरीवाल साजिश में शामिल है।

सरकारी गवाह बनाना कोर्ट तय करता है। सरकारी गवाह पर सवाल ईडी पर नहीं बल्कि कोर्ट पर है। अप्रूवर कानून 100 साल पुराना है। कोर्ट ने कहा कि कानून सभी के लिए बराबर है। कोर्ट सीएम के लिए अलग से कोई कानून नहीं बना सकता है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में केजरीवाल को गिर तार किया गया है और निचली अदालत इसे एग्जामिन करेगी। किसी को कोई विशेषाधिकार नहीं दिया जा सकता है। जांचए पूछताछ से सीएम को कोई छूट नहीं।

राउज़ एवेन्यू अदालत द्वारा उनकी न्यायिक हिरासत बढ़ाए जाने के बाद केजरीवाल 15 अप्रैल तक राष्ट्रीय राजधानी की तिहाड़ जेल में बंद हैं। केजरीवाल की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने तर्क दिया कि गिर तारी यह सुनिश्चित करने के लिए की गई है कि मु यमंत्री आगामी लोकसभा चुनावों में भाग लेने में असमर्थ हैं।

उन्होंने यह भी बताया कि ईडी अपराध की आय को केजरीवाल से जोड़ने वाला कोई भी सबूत बरामद करने में असमर्थ रहा है। ईडी ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि केजरीवाल आगामी चुनावों के आधार पर गिर तारी से छूट का दावा नहीं कर सकते। एजेंसी की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा कि यह किसी भी संदेह से परे है कि घोटाला हुआ है और मु यमंत्री को दोहरी क्षमता में गिर तार किया गया है। केजरीवाल को 21 मार्च को प्रवर्तन निदेशालय ने गिर तार कर लिया थाए जब उच्च न्यायालय ने उन्हें संघीय धन.शोधन रोधी एजेंसी द्वारा दंडात्मक कार्रवाई से सुरक्षा देने से इनकार कर दिया था। प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत की अवधि समाप्त होने पर ट्रायल कोर्ट में पेश किए जाने के बाद उन्हें 1 अप्रैल को मामले में न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था।

दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति 2021.22 विवाद के केंद्र में है। नवंबर 2021 में पेश की गई इस नीति में दिल्ली में शराब की बिक्री के तरीके में सुधार किया जाना था। इसका उद्देश्य राज्य के लिए राजस्व को अधिकतम करनाए नकली शराब की बिक्री से निपटना और उपभोक्ता अनुभव को बढ़ाना था। हालाँकिए इस नीति को जोरदार विरोध और प्रक्रियात्मक अनियमितताओं के आरोपों का सामना करना पड़ाए जिसके कारण अंततः 1 अगस्तए 2022 को इसे रद्द कर दिया गया।

केजरीवाल की याचिका खारिज होने पर बोली भाजपा, सबूतों से साफहै, वही मुख्य सूत्रधार थे

नयी दिल्ल ०९/०४ (संवाददाता): दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा उत्पाद शुल्क नीति मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी द्वारा अपनी गिर तारी को चुनौती देने वाली सीएम अरविंद केजरीवाल की याचिका खारिज होने के बादए राज्यसभा सांसद और भाजपा के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि आम आदमी पार्टी का अहंकार चकनाचूर हो गया है। अरविंद केजरीवाल का पर वार करते हुए उन्होंने कहा कि स्वघोषित कट्टर ईमानदार का किरदार धारदार तथ्यों के साथ पूरी तरह तार.तार हो गया है। उन्होंने कहा कि कोर्ट ने कहा है कि क् ने जो साक्ष्य दिए हैंए उससे साफहोता है कि अरविंद केजरीवाल शराब नीति बनाने में प्रथम सूत्रधार थे।

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आज हमारे सामने जो तीखे तथ्य उभर कर सामने आए हैंए उन्होंने केजरीवाल के स्वयंभू श्कट्टर ईमानदारश् चरित्र को पूरी तरह से कलंकित कर दिया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने आज सीएम अरविंद केजरीवाल की ईडी गिर तारी को वैध ठहराते हुए जो फैसला सुनाया हैए उससे आम आदमी पार्टी का अहंकार पूरी तरह से चकनाचूर हो गया है। उन्होंने कहा कि ईडी द्वारा एकत्र की गई सामग्री से पता चलता है कि केजरीवाल ने साजिश रची और उत्पाद शुल्क नीति तैयार करने में शामिल थे और अपराध की आय का इस्तेमाल किया।सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि वह व्यक्तिगत हैसियत सेए नीति निर्माण और रिश्वत मांगने में भी शामिल हैं और दूसरेए आप के राष्ट्रीय संयोजक की हैसियत से भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि गिर तारी के खिलाफकेजरीवाल की याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा कि यह कानून से बंधा हैए न कि राजनीतिक विचारों से। कोर्ट ने कहा कि राजनीतिक विचारों और समीकरणों को इसमें नहीं लाया जा सकताण्ण् कोर्ट केवल संवैधानिक नैतिकता को कायम रखने से चिंतित है।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने मु यमंत्री अरविंद केजरीवाल की उस याचिका को मंगलवार को खारिज कर दियाए जिसमें उन्होंने आबकारी नीति से जुड़े धनशोधन मामले में अपनी गिर तारी को चुनौती दी थी। केजरीवाल को संबंधित मामले में प्रवर्तन निदेशालय ;ईडीद्ध ने 21 मार्च को गिर तार किया था। न्यायमूर्ति स्वर्णकांता शर्मा ने फैसला सुनाते हुए कहाए अदालत का मानना ??है कि अरविंद केजरीवाल की गिर तारी कानूनी प्रावधानों का उल्लंघन नहीं है। रिमांड को अवैध नहीं ठहराया जा सकता। केजरीवाल वर्तमान में न्यायिक हिरासत में हैं।

हम इस फैसले से सहमत नहीं हैं, सुप्रीम कोर्ट जाएगी आप

०९/०४ (संवाददाता): आप नेता और दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगेए हमें सुप्रीम कोर्ट पर पूरा भरोसा है कि जैसे सुप्रीम कोर्ट से संजय सिंह को राहत मिली वैसे ही सुप्रीम कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को भी राहत मिलेगी।

आज हाई कोर्ट का फैसला आया है उसका हम स मान करते हैं और स मानपूर्वक कहते हैं कि हम इस फैसले से सहमत नहीं हैं और इसके खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और वहां अपनी बात रखेंगे। भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने ट्वीट करते हुए कहा कि मुजरिम मुजरिम होता है। देश में हर किसी को भारत के कानून का पालन करना होगा। आज माननीय न्यायालय के आदेश ने आप के गैंग लीडर को आईना दिखा दिया हैए ईडी द्वारा एकत्र किए गए सबूत बताते हैं कि सरगना अरविंद केजरीवाल हैं। आप बेनकाब हो गई है। इससे पहले दिन मेंए दिल्ली उच्च न्यायालय ने केजरीवाल की याचिका खारिज करते हुए कहा कि ईडी के पास पर्याप्त सामग्री थी जिसके कारण उन्हें गिर तार करना पड़ा। अदालत ने कहा कि मु यमंत्री की वजह से हुई देरी का असर उन लोगों पर भी पड़ा जो हिरासत में थे। अदालत ने आगे कहा कि इस अदालत की राय है कि आरोपी को गिर तार कर लिया गया है और उसकी गिर तारी और रिमांड की जांच कानून के अनुसार की जानी चाहिएए न कि चुनाव के समय के अनुसार। न्यायमूर्ति स्वर्णकांत शर्मा की पीठ ने कहाए ईडी की ओर से किसी भी दुर्भावना के अभाव में आम चुनाव से पहले गिर तारी के समय को लेकर केजरीवाल की चुनौती टिकाऊ नहीं है।

भारत बदलेगा तिब्बत के 60 जगहों के नाम, चीन को करारा जवाब देने उतरे राजनाथ

ईटानगर ०९/०४ (संवाददाता): रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन द्वारा अरुणाचल प्रदेश में कई स्थानों का नाम बदलने पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि अगर भारत ने भी इसी तरह के प्रयास किएए तो क्या इसका मतलब यह होगा कि चीन के वे क्षेत्र हमारे क्षेत्र का हिस्सा बन गए हैं। मंगलवार को अरुणाचल प्रदेश के नामसाई इलाके में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुएए राजनाथ सिंह ने कहा कि मैं चीन से पूछना चाहता हूं कि अगर हम पड़ोसी देश के विभिन्न राज्यों के नाम बदल देंगेए तो क्या वे हमारे क्षेत्र के हिस्से होंगेघ् ऐसी गतिविधियों के कारण संबंध खराब हो रहे हैं। भारत और चीन के बीच रिश्ते बिगड़ेंगे। पिछले ह ते चीन ने अरुणाचल प्रदेश में वास्तविक नियंत्रण रेखा ;एलएसीद्ध के पास विभिन्न स्थानों के 30 नए नामों की एक सूची जारी की थी। पहले भी चीन पूर्वोत्तर राज्य पर अपना दावा जताने के लिए इसी तरह की कोशिशें कर चुका है। राजनाथ सिंह ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश में 30 स्थानों के नाम बदलने के चीन के कदम से जमीनी हकीकत नहीं बदलेगी।

रक्षा मंत्री ने कहा कि हम अपने सभी पड़ोसियों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखना चाहते हैं। लेकिन अगर कोई हमारे आत्म.स मान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता हैए तो भारत उचित जवाब देने की क्षमता रखता है।ष् उन्होंने कहा कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग है।

हेमा मालिनी के खिलाफटिप्पणी के लिए कांग्रेस नेता सुरजेवाला को निर्वाचन आयोग ने भेजा नोटिस

नयी दिल्ली ०९/०४ (संवाददाता): निर्वाचन आयोग ने मंगलवार को कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला को अभिनेत्री से नेता बनीं और भारतीय जनता पार्टी ;भाजपा की सांसद हेमा मालिनी के खिलाफउनकी कथित अमर्यादित टिप्पणी के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया।

निर्वाचन आयोग ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे से भी जवाब मांगा है कि नेताओं द्वारा सार्वजनिक संवाद के दौरान महिलाओं के स मान और गरिमा को बनाए रखने के बारे में दिए गए परामर्श का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। दोनों नेताओं को निर्वाचन आयोग को जवाब देने को कहा गया है।

सुरजेवाला से 11 अप्रैल की शाम तक जवाब देने को कहा गया हैए जबकि खरगे को अगले दिन शाम तक का वक्त दिया गया है। भाजपा के आईटी प्रकोष्ठ के प्रमुख अमित मालवीय ने पिछले महीने सोशल मीडिया मंच ष्एक्सष् पर एक वीडियो साझा किया और कांग्रेस नेता सुरजेवाला पर मथुरा सीट से पार्टी की उ मीदवार हेमा मालिनी के खिलाफ ष्अपमानजनक और महिला विरोधीष् टिप्पणी करने का आरोप लगाया। बाद में भाजपा ने निर्वाचन आयोग से सुरजेवाला के खिलाफशिकायत की थी। हालांकिए सुरजेवाला ने दावा किया था कि भाजपा के आईटी प्रकोष्ठ ने झूठ फैलाने के लिए अभिनेत्री हेमा मालिनी से संबंधित टिप्पणी वाले उनके वीडियो में काट.छांट की। उन्होंने यह भी कहा था कि वह लोकसभा सदस्य हेमा मालिनी का स मान करते हैं।

मोदी सरकार में असम का हुआ विकास, अमित शाह बोले-हमने राज्य में शांति और स्थिरता लाई

गुवाहाटी ०९/०४ (संवाददाता): केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज असम में विजय संकल्प सभा में शामिल हुए। उन्होंने अपने संबोधन में लोगों से कहा कि आपको 19 अप्रैल को तय करना होगा कि आपका सांसद कौन होगाए किस पार्टी की सरकार बनेगी और अगला प्रधानमंत्री कौन होगा। उन्होंने कहा कि आपके पास दो विकल्प हैं। एक तरफ राहुल गांधी के नेतृत्व में इंडी गठबंधन है और दूसरी तरफनरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा है। उन्होंन कहा कि आपको ये तय करने के लिए वोटिंग करनी है कि आने वाले 5 साल के लिए मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे और 400 पार के लक्ष्य के साथ फिर एक बार भाजपा की सरकार बनेगी।शाह ने कहा कि कुछ दिन पहले राहुल गांधी कह रहे थे कि हमें असम की संस्कृति को बचाना है। मैं उन्हें याद दिलाना चाहता हूं कि उनकी दादी ने असम के साथ क्या किया था। हजारों युवाओं को गुमराह कर मार डाला गया। वहींए नरेंद्र मोदी ने दस से अधिक शांति समझौतों पर हस्ताक्षर किए और असम में स्थिरता लाई। 9000 से अधिक लोग आत्मसमर्पण कर मु यधारा में शामिल हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि असम में मोदी जी के 10 साल विकास के 10 साल रहे हैं। असम में पिछले 10 वर्षों में अनेक शांति समझौते हुएए विकास का काम हुआ। आने वाले दिनों में असम देश के बाकी राज्यों की तरह एक विकसित राज्य बनेगाए इसका मुझे पूरा भरोसा है। अमित शाह ने कहा कि 2004 से 2014 तक 10 साल तक देश में न्च। और कांग्रेस की सरकार थी। उस सरकार ने 10 वर्षों में सिर्फ 1 लाख 62 हजार करोड़ रुपये असम के विकास के लिए दिए थे। जबकि दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने 4 लाख 15 हजार करोड़ रुपये असम को देने का काम किया है। इसके बाद तिनसुकिया शहर में चलिहा नगर से थाना चरियाली तक एक रोडशो में भी हिस्सा लेंगे। तिनसुकिया शहर डिब्रूगढ़ सीट के तहत आता है जहां से केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल भाजपा उ मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं।

वीवीपैट पर्ची वाले वोट के सत्यापन से संबंधित याचिकाओं पर 16 अप्रैल को करेगा सुनवाई

नयी दिल्ली ०९/०४ (संवाददाता): उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को कहा कि यह षेटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेलष् ;वीवीपैट पर्ची वाले मतों का सत्यापन किये जाने का अनुरोध करने वाली याचिकाओं के एक समूह पर 16 अप्रैल को सुनवाई करेगा। ष्वीवीपैटष् स्वतंत्र रूप से वोट का सत्यापन करने वाली प्रणाली है जो मतदाता को यह देखने की अनुमति देती है कि उसका वोट उसी उ मीदवार को गया है या नहींए जिसे उसने वोट दिया है। इसके जरिये मशीन से कागज की पर्ची निकलती है जिसे मतदाता देख सकता है और इस पर्ची को एक सीलबंद लिफाफे में रखा जाता है तथा विवाद की स्थिति में इसे खोला जा सकता है।

इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ;ईवीएमद्ध से जुड़ी याचिकाएं सुनवाई के लिए नहीं ले सकी न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने कहा कि यह विषय से जुड़ी सभी याचिकाओं पर अगले मंगलवार को विचार करेगी। लोकसभा चुनाव सात चरणों में हो रहा है और पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को होना है। शीर्ष अदालत ने तीन अप्रैल को कहा था कि यह गैर सरकारी संगठन ष्एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्मर्सष् ;एडीआरद्ध द्वारा दायर याचिका की सुनवाई अन्य विषयों के साथ अगले ह ते करेगी।

वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण द्वारा तत्काल सुनवाई का अनुरोध किये जाने पर न्यायालय ने यह बात कही थी। इससे पहलेए एक अप्रैल को न्यायालय ने निर्वाचन आयोग और केंद्र से नागरिक अधिकार कार्यकर्ता अरुण कुमार अग्रवाल की एक याचिका पर जवाब मांगा था। याचिका में चुनावों में वीवीपैट की सभी पर्चियों की गिनती का निर्देश देने का अनुरोध किया गया था। वहींए वर्तमान में एक संसदीय क्षेत्र के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र से यादृच्छिक रूप से चयनित केवल पांच ईवीएम से पर्चियों का मिलान किया जाता है। दोनों याचिकाओं पर अब 16 अप्रैल को सुनवाई होगी।

एडीआर ने न्यायालय से निर्वाचन आयोग और केंद्र को यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देश जारी करने का अनुरोध किया है कि मतदाता वीवीपैट के जरिये यह सत्यापित कर सकें कि उनका वोट दर्ज हुआ मान लिया गया है। याचिका में ईवीएम का मिलान उन मतों से करने का अनुरोध किया गया है जिनका मतदान सत्यापित हो गया है और यह सुनिश्चित किया जाए कि मतदाता अपने मत को वीवीपैट पर्ची के जरिये सत्यापित करने में सक्षम हो।

Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at: http://www.software602.com/

विविध समाचार

क्या है आदर्श आचार संहिता, कब हुई थी इसकी शुरूआत, किन पर लगती है रोक?

नयी दिल्ली ०९/०४ (संवाददाता): भारत निर्वाचन आयोग ने 16 मार्च को लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों की घोषणा की। इसके साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने की आवश्यकता के लिए आयोग द्वारा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा होते ही आदर्श आचार संहिता लागू हो जाती है। देश में 543 लोकसभा सीटों के लिए 19 अप्रैल से एक जून के बीच सात चरणों में मतदान होगा। मु य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने बताया था कि चुनाव प्राधिकरण चार ष्एमष् की चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए तैयार हैद्द बाहुबल ;मसल पावरद्धए धनबल ;मनी पावरद्धए गलत सूचना ;मिसइंफॉर्मेशनद्ध और आदर्श आचार संहिता ;मॉडल कोड ऑफ कंडक्टद्ध का उल्लंघन। सीमाओं पर ड्रोन आधारित जांचए भ्रामक विज्ञापनों और फर्जी खबरों पर कार्रवाई और चुनावी हिंसा के खिलाफ ष्स तष् कार्रवाईए चारों चुनौतियों से निपटने के लिए निर्वाचन आयोग की रणनीति का हिस्सा है। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि आदर्श आचार संहिता ;एमसीसीद्ध क्या हैघ्

आचार संहिता का उद्देश्य चुनाव प्रचारए मतदान और मतगणना प्रक्रिया को व्यवस्थितए स्वच्छ और शांतिपूर्ण बनाए रखना और सत्तारूढ़ पार्टी द्वारा राज्य मशीनरी और वित्त के किसी भी दुरुपयोग को रोकना है। निर्वाचन आयोग को आचार संहिता के किसी भी उल्लंघन की जांच करने और सजा सुनाने समेत कार्रवाई करने का पूरा अधिकार है। एमसीसी का उद्गम केरल में 1960 में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान हुआ बताया जाता है जब प्रशासन ने राजनीतिक दलों के आचरण के लिए एक संहिता तैयार करने का प्रयास किया था। इसका मु य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि केंद्र और राज्यों में सत्तारूढ़ दल अनुचित बढ़त हासिल करने के लिए अपनी लाभ की स्थिति का दुरुपयोग न करें।

एमसीसी को शुरुआत में चुनाव आयोग द्वारा 1968.69 में मध्यावधि चुनावों के दौरान श्न्यूनतम आचार संहिताश् के शीर्षक के तहत पेश किया गया था। इसके बाद 1979ए 1982ए 1991 और 2013 में संशोधन किए गएए जो देश में चुनावी राजनीति की बदलती गतिशीलता को दर्शाते हैं। 1968 और 1969 के मध्यावधि आम चुनावों के दौरानए चुनाव आयोग ने राजनीतिक व्यवहार के अपेक्षित मानकों को रेखांकित करते हुए ष्चुनावों के दौरान राजनीतिक दलों की भूमिका और जि मेदारियाँष् शीर्षक से एक दस्तावेज़ तैयार किया। 1979 मेंए ष्सत्ता में पार्टियोंष् के आचरण की निगरानी करने वाले एक अनुभाग को शामिल करके एमसीसी को और अधिक समेकित किया गयाए जिसका उद्देश्य किसी भी अनुचित लाभ को रोकना था। जबकि एमसीसी ने चुनावी आचरण को विनियमित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई हैए इसके कानूनी समर्थन के बारे में चर्चा पिछले कुछ वर्षों में सामने आई है। पूर्व मु य चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी ने अपने कार्यकाल के दौरान एमसीसी को वैध बनाने की वकालत की और इसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ

कड़ी कानूनी कार्रवाई की जरूरत पर जोर दिया।

एमसीसी भारत के चुनाव आयोग द्वारा दिशानिर्देशों का एक सेट है जो बताता है कि राजनीतिक दलों और उ मीदवारों को चुनाव अभियान और मतदान के दौरान कैसा व्यवहार करना चाहिए। आदर्श आचार संहिता सभी पक्षों को ऐसी गतिविधि में शामिल नहीं होने या ऐसा भाषण नहीं देने का आदेश देती है जो विभिन्न समुदायोंए जातियों या धर्मों के बीच तनाव या नफरत पैदा कर सकता है। इसके अलावाए कोई भी पार्टी जातिए धार्मिक या सांप्रदायिक आधार पर वोट की अपील नहीं कर सकती। इसके अतिरिक्तए मस्जिदोंए मंदिरों और चर्चों जैसे पूजा स्थलों का उपयोग राजनीतिक दलों या उ मीदवारों द्वारा चुनाव प्रचार के लिए नहीं किया जा सकता है। आदर्श आचार संहिता किसी उ मीदवार के निजी जीवन की आलोचना पर रोक लगाती हैए और सभी आलोचना किसी उ मीदवार या पार्टी की नीतियोंए कार्यों और कार्यक्रमों तक ही सीमित होनी चाहिए। इसी तरहए कोई उ मीदवार या पार्टी किसी व्यक्ति के घर पर अपने विरोध के लिए प्रदर्शन या जुलूस नहीं ले जा सकती। एमसीसी का कहना है कि पार्टियों और उ मीदवारों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके समर्थक अन्य पार्टियों या उ मीदवारों की बैठक या जुलूस में बाधा न डालें। साथ हीए वे मालिकों की अनुमति के बिना निजी भूमि या इमारतों का उपयोग जुलूस या बैठकों के लिए नहीं कर सकते।

आदर्श आचार संहिता के तहत किसी पार्टी या उ मीदवार को बैठक या जुलूस आयोजित करने से पहले स्थानीय पुलिस को सूचित करना होगा। इसमें सभा और जुलूस के स्थानए समय और मार्ग के बारे में स्थानीय पुलिस को सूचित करना होगा। आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद कोई मंत्री या अन्य सत्तारूढ़ दल के नेता अपने चुनावी प्रचार के लिए विमान या वाहन जैसी आधिकारिक मशीनरी का उपयोग नहीं कर सकते हैं। साथ हीए सत्तारूढ़ दल या उसके नेता सार्वजनिक बुनियादी ढांचे जैसे मैदानए हेलीपैडए गेस्टहाउस इत्यादि पर एकाधिकार नहीं कर सकते हैं। अन्य राजनीतिक दलों या उ मीदवारों को इन स्थानों तक समान पहुंच होगी। इसके अतिरिक्तए सत्तारूढ़ दल अपने राजनीतिक प्रचार या अपनी सरकार की उपलब्धियों के लिए सरकारी खजाने की कीमत पर विज्ञापन नहीं कर सकता है।

समसामयिक मुद्दों के समाधान के लिए आदर्श आचार संहिता के दिशानिर्देश बदलते रहते हैं। सोशल मीडिया के उदय से दिशानिर्देशों में विकास हुआ है। 1 मार्च को आदर्श आचार संहिता के तहत अपने नवीनतम दिशानिर्देशों मेंए भारत चुनाव आयोग ने सोशल मीडिया प्रचार के लिए दिशानिर्देशों पर जोर दिया। इसमें कहा गया है कि कोई पार्टी या उ मीदवार अपने प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ अपमानजनक और गरिमा के खिलाफ कोई टिप्पणी पोस्ट या शेयर नहीं कर सकता। इसी तरहए समाचार या भ्रामक विज्ञापन के रूप में कोई विज्ञापन सोशल मीडिया पर साझा नहीं किया जा सकता है।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 द्वारा भारत के चुनाव आयोग को स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की निगरानी और संचालन करने की शक्ति दी गई है। आदर्श आचार संहिता पहली बार चुनाव आयोग द्वारा 1960 में केरल में विधानसभा चुनाव में पेश की गई थी। 1962 मेंए चुनाव आयोग ने आम चुनावों के लिए आदर्श आचार संहिता पेश की थी। राजनीतिक दलों द्वारा बार.बार मानदंडों के उल्लंघन के बाद 1991 में चुनाव आयोग द्वारा आदर्श आचार संहिता के दिशानिर्देशों को स त बना दिया गया था।आदर्श आचार संहिता स्वाभाविक रूप से एक अनिवार्य दिशानिर्देश है और इसे अदालत के समक्ष एक संपूर्ण नियम पुस्तिका के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता है। आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में चुनाव आयोग की चेतावनी कार्रवाई का सामान्य तरीका है।हालाँकिए यदि उल्लंघन भारतीय दंड संहिताए 1860 और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियमए 1951 के अंतर्गत आता हैए तो इसके कई गंभीर परिणाम होंगेए और उल्लंघनकर्ता को जेल भी जाना पड़ सकता है।आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद सरकार परियोजनाओं या सार्वजनिक पहल के लिए कोई नई जमीन नहीं तैयार कर सकती है। चुनावी प्रक्रिया के दौरान सरकारी निकायों को किसी भी भर्ती प्रक्रिया में भाग नहीं लेना है। चुनाव प्रचार रैलियों और रोड शो से सड़क यातायात बाधित नहीं होना चाहिए। उ मीदवारों से मतदाताओं को शराब बांटने से परहेज करने को कहा गया है। भारत में यह सर्वविदित तथ्य है कि चुनाव प्रचार के दौरान मतदाताओं को शराब वितरित की जा सकती है।

साजिश में हिस्सेदार भी और राजदार भी... आप सदस्यों ने माना गोवा चुनाव के लिए पैसे मिले

नयी दिल्ली ०९/०४ (संवाददाता): दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को दिल्ली के मु यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले में प्रवर्तन निदेशालय ;ईडीद्ध द्वारा उनकी गिर तारी को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी। न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा ने उनकी गिर तारी और उसके बाद रिमांड को बरकरार रखते हुए कहा कि ईडी पर्याप्त सामग्रीए अनुमोदकों के बयान और आप के अपने उ मीदवार के बयान पेश करने में सक्षम रही कि केजरीवाल को गोवा चुनाव के लिए पैसे दिए गए थे। इस प्रकार यह माना गया कि इस मामले में धारा 70 पीएमएलए की कठोरता आकर्षित होती है। दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा अरविंद केजरीवाल की गिर तारी को चुनौती करने वाली याचिका खारिज करने पर एएसजी एसवी राजू ने कहा कि आज जो फैसला आया वह जज ने बहुत मेहनत के बाद दिया है और न्याय किया है। कोर्ट ने

यह भी कहा है कि सबूत मिले हैं। मनी ट्रेल और मनी लॉन्ड्रिंग के भी सबूत मिले हैं। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि गिर तारी गैर कानूनी है लेकिन कोर्ट ने उनकी दलील को खारिज करते हुए कहा कि गिर तारी कानूनी है। अब कहा जा रहा है कि केजरीवाल की तरफसे राहत के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया जा सकता है। मनीष सिसोदिया सुप्रीम कोर्ट गए थे। दो बार सुप्रीम कोर्ट से उन्हें निराशा हाथ लगी थी।

जब अरविंद केजरीवाल का मामला सुप्रीम कोर्ट जाएगा तो ईडी भी अपनी तैयारी के साथ वहां जाएगी। जैसा की वो केजरीवा को इस शराब घोटाले का किंगपिन बता रही है। केजरीवाल ने ईडी द्वारा उन्हें जारी किए गए नौ समन को नजरअंदाज कर दिया था। इस मामले में आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसौदिया और संजय सिंह भी आरोपी हैं। जबकि सिसौदिया न्यायिक हिरासत में हैंए सिंह को हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी थी। अपनी गिर तारी के बादए केजरीवाल ने तुरंत अपनी गिर तारी को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक तत्काल याचिका दायर की थी। हालाँकिए बाद में इसे वापस ले लिया गया। इसके अलावाए उन्होंने पहले केंद्रीय जांच एजेंसी द्वारा उन्हें जारी किए गए समन को चुनौती देते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय ;डिवीजन बेंचद्ध का रुख किया था। उन्होंने अंतरिम सुरक्षा की मांग करते हुए एक आवेदन भी दायर किया है। मामले की सुनवाई 22 अप्रैल को तय की गई है। केजरीवाल ने समन को यह कहते हुए नजरअंदाज कर दिया कि यह अवैध है। ईडी का मामला है कि कुछ निजी कंपनियों को थोक व्यापार में 12 प्रतिशत का लाभ देने की साजिश के तहत उत्पाद शुल्क नीति लागू की गई थीए हालांकि मंत्रियों के समूह ;जीओएमद्ध की बैठकों के मिनटों में ऐसी शर्त का उल्लेख नहीं किया गया था।

चैत्र नवरात्र के पहले दिन वैष्णो देवी मंदिर में हजारों श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़

जमू ०९/०४ (संवाददाता): देश भर से हजारों श्रद्धालु मंगलवार को नौ दिवसीय चैत्र नवरात्र शुरू होने के उपलक्ष्य में ज मू.कश्मीर के रियासी जिले में स्थित माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए पहुंचे। बॉर्ड के एक प्रवक्ता ने बतायाए श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बॉर्ड ;एसएमवीडीएसबी के द्वारा इस शुभ अवसर पर वैष्णो देवी की पवित्र गुफा में शांत वातावरण के बीच शत चंडी महायज्ञ का आयोजन किया गया। साथ ही अन्य अनुष्ठान भी किये गये। उन्होंने कहा कि त्रिकुटा पहाड़ी के ऊपर स्थित इस मंदिर में सभी के लिए सद्भाव और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करने के

लिए पूरी नवरात्रि में पवित्र अनुष्ठान किये जायेंगे। प्रवक्ता ने बताया कि एसएमवीडीएसबी के मु य कार्यकारी अधिकार अंशुल गर्ग तीर्थयात्रियोंए बोर्ड के अन्य सदस्यों और अधिकारियों के साथ इस यज्ञ में शामिल हुए। उन्होंने बताया कि नौ दिनों तक प्रतिदिन दोपहर 12 बजे से एक बजे तक एमएच1 श्रद्धा चैनल पर हवन का सीधा प्रसारण किया जाएगा।

नवरात्र के शुभ अवसर पर माता वैष्णो देवी मंदिर को रंग.बिरंगी रोशनीए फूलोंए पारंपरिक रूपांकनों और अलंकरणों के साथ सजाया गया है। प्रवक्ता ने बताया कि बोर्ड ने ज मू.कश्मीर के उपराज्यपाल और एसएमवीडीएसबी के अध्यक्ष मनोज सिन्हा के निर्देशों के अनुसार नवरात्र के दौरान मंदिर में आने वाले बड़ी सं या में तीर्थयात्रियों की सुविधा के लिए विशेष प्रबंध किये हैं।

उन्होंने कहा कि खास व्यवस्थाओं के तहत मंदिर की ओर जाने वाले रास्ते पर चौबीसों घंटे पानी और बिजली की आपूर्तिए स्वच्छता और चिकित्सा सुविधाएं और बोर्ड के भोजनालयों में विशेष व्रत वाला भोजन उपलब्ध कराया गया है। उन्होंने कहाए तीर्थयात्रियों की सुविधा के लिए आवासए बैटरी चालित वाहनए रोपवे और हेलीकॉप्टर सेवाएं जैसी सुविधाएं प्रदान की गई हैं और ये सुचारू रूप से चल रही हैं।

भैरों जी में लंगर सेवा के अलावा तीर्थयात्रियों को ताराकोटे मार्ग और सांझीचट्ट में प्रसाद केंद्र पर मु त भोजन भी उपलब्ध कराया जाएगा। अधिकारी ने कहा कि बोर्ड द्वारा दिव्यांग श्रद्धालुओं की तीर्थयात्रा को आसान बनाने के लिए मंदिर में मु त टट्टू और बैटरी कार सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि वैष्णो देवी मंदिर में नवरात्र के अवसर पर प्रसिद्ध कलाकारों द्वारा भजन और अटका आरती का भी आयोजन किया गया है।

नवरात्र में नौ दिनों तक होगी शक्ति की उपासना

नयी दिल्ली ०९/०४ (संवाददाता): चैत्र नवरात्र की शुरुआत नौ अप्रैल को हो गई है। देश भर में धूमधाम के साथ नवरात्र का त्योहार मनाया जा रहा है। इस बार प्रभु श्रीराम की नगरी अयोध्या में भी चैत्र नवरात्र मनाया जा रहा हैए जिसके नवमी के दिन रामनवमी मनाई जाएगी। ये पहला मौका है जब राम मंदिर में धूमधाम के साथ रामनवमी मनाई जाएगी। ये पहला मौका है जब रामनवमी से पहले नवरात्र के लिए चांदी की चौकी पर कलश स्थापना भी की गई है। बता दें कि रामनमवी से पहले नवरात्र के दौरान नौ दिनों तक प्रभुराम के दरबार में देवी देवताओं की पूजा आराधना होगी। इस दौरान राम मंदिर में दुर्गा सप्तशती का पाठ होगा। नवरात्र के दौरान राम मंदिर में खास व्यवस्थाएं की गई है। नवरात्र मनाने के लिए इस बार राम मंदिर में रामलला को 56 व्यंजनों का भोग लगाया जाएगा। चैत्र नवरात्रि में मनने वाली रामनवमी की भी खास तैयारियां की जा रही है। रामनवमी इस बार बेहद अद्भुत और अलौलिक होने वाली है। बता दें कि रामनवमी इस वर्ष 17 अप्रैल की दोपहर 12 बजे से पहले रामलला अपने भव्य महल में जन्म लेंगे। नवरात्र के नौ दिनों तक रामलला के दरबार में खास पूजा अर्चना होगी। दुर्गा सप्तशती का पाठ होगा। नौ दिनों तक व्यंजनों का भोग लगाया जाएगा। प्रभु श्रीराम और देवी देवताओं का विधि विधान के साथ पूजन होगा। नवरात्र के लिए खास पूजन विधि बनाई गई हैए जिसके मुताबिक ही पूजन किया जाएगा। रोजाना वेद मित्रों से हवन कुंड में आहुतियां डाली जाएंगे।

खड़गे बोले–मोदी के राजनीतिक पूर्वज मुस्लिम लीग के समर्थक, जेपी नड्डा ने किया पलटवार

नयी दिल्ली ०९/०४ (संवाददाता): कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस के घोषणापत्र की आलोचना करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। खड़गे ने कहा कि मोदी.शाह के राजनीतिक और वैचारिक पूर्वजों ने स्वतंत्रता संग्राम में भारतीयों के खिलाफब्रिटिश और मुस्लिम लीग का समर्थन किया था। नरेंद्र मोदी के आरोप पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक लंबा एक्स पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा कि मोदी.शाह के राजनीतिक व वैचारिक पुरखों ने स्वतंत्रता आंदोलन में भारतियों के ख़िलाफ़ए अंग्रेज़ों और मुस्लिम लीग का साथ दिया। आज भी वो आम भारतियों के योगदान से बनाए गए श्कांग्रेस न्याय पत्रश् के ख़िलाफ़मुस्लिम लीग की दुहाई दे रहे हैं। खड़गे ने कहा कि

मोदी.शाह के पुरखों ने 1942 में ष्भारत छोड़ोष् के दौरानए महात्मा गांधी के आवाहन व मौलाना आज़ाद की अध्यक्षता वाले आंदोलन का विरोध किया। सभी जानते है कि आपके पुरखों ने 1940श्े में मुस्लिम लीग के साथ मिलकर बंगालए सिंध और छ्थ्थ्च् में अपनी सरकार बनाई।क्या श्यामा प्रसाद मुख़र्जी ने तत्कालीन अंग्रेज़ी गवर्नर को ये नहीं लिखा कि 1942 के देश व कांग्रेस के भारत छोड़ो आंदोलन को कैसे दबाना चाहिएघ् और इसके लिए वे अंग्रज़ों का साथ देने के लिए तैयार हैघ् अपना वार जारी रखते हुए खड़गे ने कहा कि मोदी.शाह व उनके मनोनीत अध्यक्ष आज कांग्रेस घोषणापत्र के बारे में उल्टी.सीधी भ्रांतियां फैला रहें हैं।

मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मोदी जी की भाषणों में केवल आरएसएस की बू आती हैए दिन पर दिन भाजपा की चुनावी हालत इतनी खस्ता होती जा रही हैए कि आरएसएस को अपने पुराने मित्र . मुस्लिम लीग . की याद सताने लगी है! सच केवल एक है . कांग्रेस न्याय पत्र में हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोगों की आशाओं व आकांक्षाओं की छाप है। उनकी स मिलित शक्तिए मोदी जी के 10 सालों के अन्याय काल का अंत करेगी।

जेपी नड्डा ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस का घोषणापत्र विभाजन का खाका हैए जिन्ना के मुस्लिम लीग एजेंडे की स्पष्ट प्रतिकृति है। राष्ट्रीय एकता पर तुष्टिकरण की राजनीति को प्राथमिकता देकरए कांग्रेस विभाजन को कायम रखना चाहती है। भारत ने पहले भी ऐसी विभाजनकारी राजनीति को खारिज किया है और फिर भी ऐसा करेगा। भाजपा ध्रुवीकरण के इस खतरनाक रास्ते के खिलाफ मजबूती से खड़ी है और सभी के लिए समावेशी शासन के लिए प्रतिबद्ध है।

कलिंग समाचार
THE KALINGA SAMACHAR
(A Hindi Daily News Paper)
PUBLISHED FROM ODISHA, JHARKHAND &CHATTISHGARH
FOR NEWS AND ADVERTISEMENT CONTACT
AT: QRS. NO. B/204, SECTOR-16
ROURKELA, PH. 0661-2646999
PRAKASH KUMAR DHAL (EDITOR)
E-mail: thekalingasamachar@gmail.com

Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at: http://www.software602.com/
kalinga pg-2 for 10-APR.pmd 1 4/10/2024, 12:43 PM

विविध समाचार

फैशनेबल ड्रेसेज और एक्सेसरीज से भरा रहे आपका वॉर्डरोब

फैशन ट्रेंड की भविष्यवाणी थोड़ा मुश्किल काम है। आज जो ट्रेंड है, वह कल होगा या नहीं, इसके बारे में पूरी तरह से कुछ भी नहीं कहा जा सकता। लेकिन यह भी पूरी तरह से सच नहीं है कि आप लिमिटेड फैशन को फॉलो न कर सकें। ऐसे भी कुछ बेसिक आइटम्स की जरूरत हमेशा बनी रहती है। इन्हें अपने वॉर्डरोब में शामिल करके अपने वॉर्डरोब को फैशनेबल बना सकती हैं। आप अपने वॉर्डरोब में कुछ टाइमलेस ड्रेसेज, जॉगर्स और फुटवियर्स शामिल करें, ये आपके काम आएंगे।

हर किसी की चाहत होती है कि उसका वॉर्डरोब फैशनेबल ड्रेसेज और एक्सेसरीज से भरा रहे। अपने वॉर्डरोब को फुल करने के चक्कर में लोग अक्सर भूल जाते हैं कि फैशन का ट्रेंड बदलता रहता है। ऐसे में सबसे बेस्ट ऑप्शन यह है कि एक टाइमलेस वॉर्डरोब के बारे में सोचा जाए।

वाइट शर्ट

फैशन डिजाइनर [illegible] की मानें, तो वॉर्डरोब के लिए वाइट टेलर्ड शर्ट सबसे जरूरी है। दरअसल, वाइट शर्ट या टॉप के साथ कुछ भी मैच करके पहना जा सकता है। वाइट शर्ट के साथ कोई भी एक्सेसरीज आसानी से मैच हो जाती है। आप चाहें तो वाइट शर्ट में डिफरेंट कट्स, स्टाइलिश स्लीव्स या फंकी कॉलर्स डिजाइन करवा सकती हैं। वहीं, फैब्रिक में सिल्क, शिफॉन व कॉटन [illegible] करें। इन फैब्रिक्स में फिटिंग भी बहुत अच्छी आती है और इन्हें हर सीजन में पहना जा सकता है।

शिफ्ट ड्रेसेज

अक्सर लड़कियां किसी ओकेजन को ध्यान में रखकर ड्रेस परचेज करती हैं। वहीं वजह है कि अगर उन्होंने ऑफिस ओकेजन के लिए ड्रेस ली है, तो वह उसे नाइट पार्टी में पहनना बिल्कुल पसंद नहीं करती हैं। ऐसे में शिफ्ट ड्रेसेज बेस्ट ऑप्शन हैं। इन्हें आप डे व नाइट दोनों मौकों पर पहन सकती हैं। दरअसल, एक शिफ्ट ड्रेस से भी वैरिएशन क्रिएट किया जा सकता है। जरूरी यह है कि उसे एक्सेसरीज के साथ कैसे कैरी किया जाए। शिफ्ट ड्रेसेज पहनने से फेमिनिन लुक तो आता ही है तथा इन्हें कैरी करके आप और भी ज्यादा स्टाइलिश लग सकती हैं।

जैकेट

यदि आप एक ही ड्रेस पहनकर बोर हो गई हैं तो जैकेट के साथ एक्सपेरिमेंट कर सकती हैं। इन दिनों मिलिट्री जैकेट ट्रेंड में है। इन्हें आप सॉलिड कलर्स में ले सकती हैं। इससे आपको क्लासिक लुक मिलेगा। यदि आप नाइट आउट पर जा रही हैं तो लाइनी जैकेट बेस्ट ऑप्शन है। इसे आप जीन्स के साथ मैच करके पहन सकती हैं। इससे आपको पूरा पार्टी लुक मिलेगा और आप काफी स्टाइलिश लगेंगी।

ब्लैक ड्रेसेज

कोई भी वॉर्डरोब ब्लैक ड्रेसेज के बिना कम्प्लीट नहीं होता है। इसे किसी भी ओकेजन पर पहना जा सकता है। चाहे आप [illegible] लुक में दिखना चाहती हों, ब्लैक ड्रेस के साथ हल्की-फुल्की ज्वेलरी कैरी करें। इसका मिक्स एंड मैच स्टाइल से खुद को डिफरेंट लुक दिया जा सकता है। ब्लैक ड्रेस के साथ सिल्वर ज्वेलरी बहुत फबती है। आप इसके साथ अपने वॉर्डरोब में ट्रेंडी लुक भी शामिल कर सकती हैं। इसके कलर सीजन के मुताबिक चुनें। इन्हें आप सिल्वर, गोल्ड और पेस्टल कलर में चुन सकती हैं। यह आपकी पर्सनैलिटी पर खूब फबेगा।

जींस

हर किसी के पास एक पेयर जींस होना लाजमी है, लेकिन उसका फिट होना भी बहुत जरूरी है। फैशन डिजाइनर [illegible] कहती हैं जींस हर सीजन में और हर ओकेजन में पहन सकती हैं। यह जरूरी नहीं है कि जींस ब्लैक ही हो। आप जींस के साथ खूब एक्सपेरिमेंट भी कर सकती हैं। अगर आप कैजुअल आउटिंग पर जा रही हैं, तो इसके साथ बैगी टी-शर्ट व स्नीकर्स पहन सकती हैं। यदि आप को पार्टी में जाना है तो जींस के साथ स्टाइलिश टॉप और [illegible] कर सकती हैं। बस ध्यान रखें कि जींस की क्वॉलिटी अच्छी हो।

पर्ल

[illegible] परफेक्ट हैं। वैसे ही पर्ल भी कभी फैशन से आउटडेटेड नहीं होते हैं। आप एक्सेसरीज में पर्ल नेकलेस या ब्रेसलेट्स जरूर रखें। इन्हें आप हर तरह के आउटफिट्स के साथ कैरी कर सकती हैं। अगर आप सिंगल पर्ल नेकलेस पसंद नहीं करती हैं तो [illegible] नेकलेस खरीद सकती हैं।

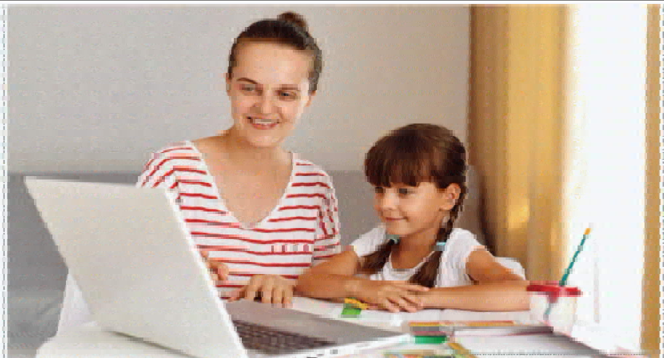

बच्चे को सारी सुविधाएं देने के साथ-साथ उन पर निगरानी

प्रतिस्पर्धा और दिखावे के मौजूदा दौर में अभिभावकों की इच्छा होती है कि उनका बच्चा किसी भी मामले में कम न रहे। इसके चलते वे अपनी संतानों को सहूलियत, पढ़ाई और 'जमाने के साथ चलने' के नाम पर विभिन्न चीजें प्रदान करते हैं, कई बार तो सामर्थ्य से भी बढ़कर। वैसे तो कोई भी वस्तु या सुविधा अपने आप में बुरी नहीं होती, लेकिन [illegible] इस्तेमाल पर निर्भर कर सकते हैं कि वह लाभदायक होगी या हानिकारक। बच्चों पर मोबाइल फोन, गाड़ी, इंटरनेट कनेक्शन, ओटीटी सब्सक्रिप्शन, क्रेडिट कार्ड आदि सुविधाओं के असर का आकलन इन पैमानों पर किया जा सकता है कि उसे फायदे की जगह नुकसान तो नहीं हो जाएगा और माता-पिता के लिए अप्रिय स्थिति तो पैदा नहीं हो जाएगी।

कई बार काम में व्यस्त माता-पिता छोटे बच्चों को बहलाए रखने या मनोरंजन के लिए मोबाइल फोन थमा देते हैं। इस उम्र में मोबाइल की चमकती स्क्रीन बच्चे की आंखों पर स्थायी रूप से बुरा असर छोड़ सकती है। इसके अलावा, उसके सामाजिक समायोजन और भाषा के विकास पर भी दुष्प्रभाव पड़ता है। स्क्रीन की हलचल और किरदारों की नाटकीयता के चलते भावनाओं का प्रदर्शन और एकाग्रता भी प्रभावित होती है। इस दौरान भले ही बच्चा शांत बैठा रहे, पर यह उसके शारीरिक विकास को अवरुद्ध करता है। हर बार मोबाइल थमा दिए जाने से उसमें जिद करने और अपनी बात मनवाने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है।

6-12 वर्ष

इस उम्र के पढ़ाई के नाम पर मोबाइल फोन और इंटरनेट की सुविधा दी जाने लगी है। वैसे तो कोरोना के ऑनलाइन दौर में यह मजबूरी थी, परंतु अब इसकी कोई आवश्यकता नहीं लगती। विशेषज्ञ कहते हैं कि बढ़ते बच्चों को इंटरनेट पर फटाफट सर्च करके बने-बनाए नतीजे हासिल करने के बजाय मेहनत करके किताबों से खोजने की आदत डालनी चाहिए। इससे उनकी बुनियाद मजबूत होगी। यही वजह है कि तमाम कैलकुलेटर उपलब्ध होने के बावजूद बच्चों से गणित का अभ्यास कराया जाता है और तथ्य याद कराए जाते हैं। इस उम्र में इंटरनेट की अधिक मदद लेने से परिश्रम करने, दिमाग लगाने, चीजों को समझने की प्रवृत्ति कम हो जाती है, आंखों को नुकसान पहुंचता है सो अलग। दूसरी तरफ, मोबाइल गेम, सोशल मीडिया और विभिन्न तरह के वीडियो देखने की लत भी लग सकती है। समझ के अभाव में कई बार बच्चे ऑनलाइन गलत लोगों से दोस्ती कर लेते हैं और साइबर बुलिंग या धोखाधड़ी का शिकार हो जाते हैं। [illegible] उनके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर डालती है। इससे बच्चों में नींद और एकाग्रता की कमी भी देखी जाती है।

13-18 वर्ष

किशोरावस्था के इस दौर में अभिभावकों को बच्चे की जरूरत के साथ-साथ उसके शौक, फैशन और पीयर प्रेशर का ध्यान भी रखना होता है। इस उम्र में मोबाइल फोन और इंटरनेट के अलावा ड्राइविंग लाइसेंस, क्रेडिट कार्ड जैसी चीजें भी दिलाई जाने लगती हैं। इस समय इंटरनेट की सीमित जरूरत हो सकती है, लेकिन बड़ों की निगरानी में और सिर्फ पढ़ाई के उद्देश्य से। ऐसा न हो कि इंटरनेट के असीमित प्रयोग से बच्चा काल्पनिक और काल्पनिक दुनिया में उलझ कर रह जाएगा और संभव है कि वास्तविक दुनिया से उसका संपर्क कट जाए। अभिभावकों की निगरानी न होने पर ऑनलाइन गेम, अनजान लोगों से दोस्ती, पॉर्न की लत जैसे बुरे असर भी हो सकते हैं। जहां तक स्मार्टवॉच जैसी सुविधा का सवाल है, तो यह स्कूल में भी ध्यान भटकाएगी और स्मार्टफोन से ज्यादा जोड़े रखेगी, जिसका कोई लाभ नहीं है। उन्हें वाहन देना भी जोखिम भरा हो सकता है, क्योंकि इस उम्र में रोमांच की चाह तो होती है, पर निर्णय क्षमता तात्कालिकता के नतीजों की समझ पूर्ण विकसित नहीं होती। एक अध्ययन का निष्कर्ष है कि वयस्कों की तुलना में किशोरावस्था वाहन चालकों से दुर्घटना की आशंका चार गुना अधिक होती है।

18 वर्ष से अधिक

इस उम्र में बच्चे पढ़ाई के लिए कई बार अपने घर से दूर भी जाकर रहते हैं, इसलिए मोबाइल फोन, इंटरनेट, गाड़ी के साथ-साथ क्रेडिट कार्ड जैसी सुविधा भी जरूरी लगने लगती है। हालांकि इनको पूरी तरह वर्जित नहीं किया जा सकता, लेकिन उपयोग को सीमित अवश्य किया जाना चाहिए। जैसे, क्रेडिट की एक लिमिट होनी चाहिए और इसे अभिभावक के फोन नंबर से लिंक होना चाहिए, ताकि हर खर्च की जानकारी उन तक पहुंचे। वाहन भी दिखावे के बजाय आवागमन में सुविधा के लिए खरीदा जाना चाहिए।

बदलाव ऐसे लाएं

अक्सर देखा गया है कि जब बच्चे सुविधाओं का दुरुपयोग करने लगते हैं तो अभिभावक उनसे वह सब वापस ले लेते हैं। इससे बच्चे विद्रोही भी हो जाते हैं। ऐसे मामलों में माता-पिता इन बातों का ध्यान रखें-

- माता-पिता पहले बच्चों के साथ बातचीत करें और उन्हें समझाएं कि इस सुविधा को कम करने या वापस लिए जाने की आवश्यकता क्या है।
- नियम बनाएं कि छोटे बच्चे मोबाइल फोन का इस्तेमाल अभिभावक की निगरानी में ही करेंगे और जिस काम से मोबाइल लिया गया है, उसी तक सीमित रहेंगे।
- ओटीटी प्लेटफॉर्म पर नकारात्मक और हिंसक कार्यक्रमों के लिए [illegible] करें। ओटीटी प्लेटफॉर्म, सर्च इंजन, वीडियो आधारित सोशल मीडिया पर रिस्ट्रिक्टेड मोड का प्रयोग करके अनुचित वेबसाइट/कंटेंट को अवरुद्ध किया जा सकता है।
- कोई भी चीज या सुविधा कभी भी सजा के तौर पर वापस न लें।
- बच्चों से यह स्पष्ट कर दें कि प्राइवेसी के नाम पर असीमित छूट नहीं दी जाएगी। खासतौर पर सोशल मीडिया पर माता-पिता फ्रेंडलिस्ट में रहेंगे और आवश्यकता होने पर फ्रेंड्स के बारे में जानकारी भी लेंगे।
- सही तरीके से सुविधाओं का उपयोग करने पर माता-पिता बच्चों की प्रशंसा भी करें।
- हर सुविधा के उपयोग के लिए एक उपयुक्त समय सीमा निर्धारित करें। बच्चों के साथ-साथ माता-पिता भी अपने लिए सभी सुविधाओं के उपयोग का समय निश्चित रखें।
- बच्चों को सही और गलत में अंतर करना सिखाएं तथा उन्हें समय-समय पर नैतिक मूल्यों से अवगत कराएं।

प्रकृति और महिलाएं एक-दूजे की पर्याय

लगातार बढ़ता तापमान, सूखते जलस्रोत और प्रदूषित होता वायुमंडल यह सब संकेत हैं कि आने वाला समय और भी कठिन संकट ला सकता है।

लगातार बढ़ता तापमान, सूखते जलस्रोत और प्रदूषित होता वायुमंडल यह सब संकेत हैं कि आने वाला समय और भी कठिन संकट ला सकता है। तो क्यों ना संभलते हुए इन सब समस्याओं से निपटने के प्रयास किए जाएं क्योंकि छोटे-छोटे प्रयास ही सार्थक होकर किसी बड़े कार्य को पूर्ण करेंगे। शायद पर्यावरण बचाव के यज्ञ में हर एक का योगदान एक-एक आहुति से कम न हो।

एक वृक्ष पहल

हमारे देश में प्रकृति व पृथ्वी को मां का दर्जा दिया है। सिर्फ इसलिए कि वे अपने पुत्रों व परिवार के संरक्षण के लिए समर्पित हैं इसलिए क्यों न हम अपने परिवार में एक ऐसी संस्कृति की शुरुआत करें जो प्रकृति के संवर्धन में भी जुटे और अपने पारिवारिक उत्सव को पर्यावरण संरक्षण से भी जोड़ सके। हमारे एक महत्वपूर्ण दर्जे के रूप में [illegible] है परिवार के प्रत्येक व्यक्ति के जन्मदिन के शुभ अवसर पर वृक्षारोपण कर पृथ्वी के उस कर्ज की मुक्ति का रास्ता भी खोला जा सकता है। जितनों हमने जो कुछ प्रकृति से लिया है या लेते उसकी [illegible]। इससे प्रकृति प्रेम भी पनपेगा और आने वाली पीढ़ी के लिए संस्कार भी तैयार होंगे। इसी तरह परिवार के अन्य कार्यों जैसे शादी, ब्याह, मुंडन [illegible] किसी कार्य से जोड़ लेना चाहिए। ऐसा ही करके शायद हम अपनी प्रकृति को बचा पाएंगे और आने वाली पीढ़ी को अपनी परंपराओं का हिस्सा बना पाएंगे।

बिन पानी सब सून

बूंद-बूंद पानी की तरस को इस वर्ष देशभर के 11 राज्यों के 33 करोड़ लोगों ने देखा है। सबसे बुरे हालात महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश एवं कर्नाटक के गांवों में रहे, जहां गांव के गांव [illegible] हो गए। वहीं [illegible] के लिए रेल के जरिए पानी भेजा गया। यदि इसी तरह के हालात रहे तो यह सभी के लिए दुखदायी होंगे। इसलिए हम सभी को यह सोचना होगा कि जल पानी के बिना का सूना है तो क्यों न बूंद-बूंद से [illegible]। जब तक इस सबक नहीं होंगे तब तक और किसी को नहीं सिखाया जा सकता है। तो क्यों न हम पानी बचाने की शुरुआत घर से ही प्रारंभ की जाए। [illegible] रखने के उपाय अपनाने होंगे तभी तो हम इसका संरक्षण कर पाएंगे।

महिलाओं का योगदान

इतिहास को खंगालें तो ज्यादा दूर [illegible] पर्यावरण की रक्षा में हमेशा से महिलाओं को ही अग्रणीय पाया गया है। विश्व प्रसिद्ध चिपको आंदोलन की प्रणेता गौरा देवी गांव की सरल महिला थीं, जिनकी [illegible] प्रसिद्ध हुई। आखिर पूरे हिमालय में वनों के प्रति यह संवेदनशीलता उस महिला को ही क्यों जगी? [illegible] था! बात गौरा देवी की ही नहीं बल्कि राजस्थान के विश्नोई समुदाय की भी है, जहां महिलाओं ने पेड़ों पर [illegible] का विरोध किया था। आखिर नोबेल पुरस्कार विजेता अफ्रीका की वंगारी माथाई को ही करोड़ों वृक्षों की लगाने को याद क्या जाए। ऐसे ही अपने देश में [illegible] हैं, जिनमें महिलाएं वृक्षों के प्रति गंभीर संवेदनशीलता दर्ज कर चुकी हैं। इतिहास गवाह है कि वन लगाने की बात हो या फिर [illegible] पर महिलाएं ही अग्रणी रही हैं। इसलिए पर्यावरण की सुरक्षा में सबसे पहले महिलाओं को ही याद किया जाता है ताकि उनके और [illegible] भी कुछ बेहतर प्रयास कर सकें। असल में इसका कारण वृक्ष और महिलाओं की समान प्रवृत्तियां हैं। दोनों ही [illegible] के लिए समर्पित हैं। दोनों के ही [illegible] हैं। महिला और वृक्ष समाज के सृजन व बेहतरी के लिए बिना किसी शर्त के [illegible] हैं। [illegible] इसलिए यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि दोनों के बिना प्रकृति पृथ्वी और समाज [illegible]। [illegible] बल्कि पूरक भी हैं और अगर ऐसा नहीं होता तो क्यों महिलाएं वनों व वृक्षों [illegible]। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें प्रकृति व प्रवृत्ति की समान झलक दिखाई देती है।

आपके पूरे घर को रीप्रेज़ेंट करता है लिविंग रूम

घर का लिविंग रूम वह कमरा होता है जो आपके पूरे घर को रीप्रेज़ेंट करता है। इसे सजाने के लिए आप अपनी पसंद की चीजें लगाते हैं, उसे अलग-अलग कलर स्कीम और पैटर्न्स से सजाते हैं।

जब आपके किसी के घर मेहमान बन कर जाते हैं तो उनका लिविंग रूम देखकर ही आप पूरे घर का अंदाजा लगा लेते हैं। वैसे ही जब कोई आपके घर आता है तो भी यही बात मायने रखती है। कहने का तात्पर्य यह है कि घर का लिविंग रूम वह कमरा होता है जो आपके पूरे घर को रीप्रेजेंट करता है। इसे सजाने के लिए आप अपनी पसंद की चीजें लगाते हैं, उसे अलग-अलग कलर स्कीम और पैटर्न्स से सजाते हैं। आपकी सजावट पर हमें कोई शक नहीं है बस हम आपके ज्ञान में थोड़ी वृद्धि कर रहे हैं कि कैसे आप अपने लिविंग रूम को और बेहतर बना सकती हैं।

- कंट्रास्ट- लिविंग रूम में दीवारों पर कंट्रास्ट कलर ट्राई करें या दो रंगों से दीवारों को रंगें। यह रूम को थोड़ा स्टार्क लुक देगा। रंगों में लाइट-डार्क, ब्लैक-व्हाइट, रेड-व्हाइट का कॉम्बिनेशन ले सकते हैं। इन्हीं में से किसी कलर कॉम्बिनेशन को चुन कर आप पूरे कमरे के लुक को दिलचस्प कर सकती हैं।
- फूलदान - लिविंग रूम की सेंटर टेबल पर फूलों का गुलदस्ता रखें। इसके लिए असली फूलों के साथ विशेष अवसर पर प्राकृतिक फूलों का इस्तेमाल करें। यह लिविंग रूम को सजाने का सबसे आसान और सीमित बजट में निपटने वाला तरीका है।
- फोटो फ्रेम- अपने लिविंग रूम को कलात्मक और [illegible] टच देने के लिए दीवार पर अपनी फैमिली की फोटो लगा सकते हैं। चाहें तो पूर्वजों की तस्वीरों को भी लिविंग रूम में जगह दे सकते हैं। इससे निश्चित रूप से आपके लिविंग रूम में शांति और सौम्यता का वातावरण आ जाएगा।
- पर्दे- लिविंग रूम में पर्दे जरूर लगाएं [illegible] कि वे कमरे में आनेवाले प्राकृतिक उजाले को ना रोकें। आजकल पारदर्शी पर्दे चलन में हैं आप उन्हें इस्तेमाल कर सकती हैं या फिर अगर कुछ अलग करना चाहती हैं तो कॉटन से बने पर्दे लगाएं। ये मनचाहे रंग में मिल जाएंगे और कमरे में अंधेरा भी नहीं करेंगे और आपका कमरा शानदार दिखेगा।
- सेटअप- अपने फर्नीचर और एक्सेसरीज का सेटअप बुद्धिमत्तापूर्ण तरीके से करें। कमरा अव्यवस्थित भरा हुआ ना लगे इसका खास ध्यान रखें। अच्छी लाइटिंग स्कीम चुनें। इस बात का ध्यान रखें कि कमरा व्यवस्थित लगे। साफ-सुथरा हो।

Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at: http://www.software602.com/
kalinga pg-3 for 10-APR.pmd 1 4/10/2024, 10:08 AM

कलिंग समाचार

संपादकीय

बुधवार 10 अप्रैल 2024

और भी जानलेवा होती भारतीय सड़कें

एक ओर तो भारत सरकार सड़क यातायात को सुगम और सुरक्षित साबित करने के बड़े दावे करती है परन्तु वास्तविकता यह है कि भारतीय सड़कें बेहद असुरक्षित हैं जो हर रोज न जाने कितने लोगों के जीवन को लील रही है और लोगों को घायल कर रही हैं। इनमें से बड़ी सं या में ऐसे भी हैं जो आजीवन विकलांग या शारीरिक रूप से पूरी तरह असमर्थ हो जाते हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा भारत में 2022 के दौरान होने वाले सड़क हादसों को लेकर जो वार्षिक रिपोर्ट जारी की गई है वह बेहद चिंताजनक है। स्थिति की ग भीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि भारत में कहीं न कहीं औसतन हर घंटे 53 दुर्घटनाएं होती हैं जिनमें 19 लोगों की मौत हो जाती है। ये आंकड़े चेतावनी के रूप में लिये जाने चाहिये और इन दुर्घटनाओं को टालने के लिये असरकारी कदम उठाने होंगे। सड़कें न केवल सुरक्षित हों वरन वाहनों की स्थिति भी ठीक होना चाहिये तथा वाहन चालन भी दोषरहित हो तभी सड़क यातायात को सुरक्षित कर नागरिकों के अमूल्य जीवन बचाये जा सकते हैं। हर वर्ष राज्यों तथा केंद्रशासित प्रदेशों के पुलिस विभागों द्वारा ऐसी रिपोर्ट जारी होती है। साल 2022 के आंकड़े सड़क दुर्घटनाओं और उनके चलते होने वाली मौतों की सं या व घायलों की तादाद में बड़ी बढ़ोतरी को दर्शाते हैं। ये आंकड़े एशिया पेसिफिक्र रोड एक्सीडेंट डाटा के अंतर्गत जारी किये गये हैं। इसके अनुसार साल 2022 के दौरान देश भर में 4ए61ए312 सड़क दुर्घटनाएं हुईं। इनमें 1ए68ए491 लोगों की मौत हुई और 4ए43ए366 लोग घायल हुए। उसके पहले साल की तुलना में दुर्घटनाएं 11ण्9 प्रतिशत बढ़ी हैं। 9ण्4 फीसदी अधिक लोगों की मृत्यु हुई जबकि घायलों की सं या के लिहाज से यह 15ण्3 प्रश की वृद्धि है. रिपोर्ट में सड़क हादसों का सबसे बड़ा कारण निर्धारित गति से भी तेज चालनए नशे में गाड़ी चलाना और यातायात नियमों का अनुपालन न करना बताया गया है। सड़क हादसों को लेकर वाहन चालकों को जागरूक करने की ज़रूरत बतलाई गई है। उनके लिये शैक्षणिक व प्रशिक्षण अभियान भी आवश्यक बताये गये हैं। सवाल तो यह है कि कुछ वर्षों पहले भारत सरकार ने नियम तोड़ने वालों के लिये बड़े जुर्माने निर्धारित किये थे। विशेषज्ञों ने तभी यह राय जाहिर की थी कि भारी.भरकम आर्थिक दण्ड की बजाय जागरूकता बेहतर उपाय है। मंत्रालय का यह भी दावा रहा है कि सड़क हादसों को रोकने के लिए कई तरीके अपनाए जा रहे हैं जिनमें मंत्रालय द्वारा वाहन चालकों को प्रशिक्षण देना आदि शामिल है। इसके अलावा वह सड़कों की गुणवत्ताए वाहन के मानकए यातायात नियमों का कड़ाई से अमल सहित दुर्घटनाओं को रोकने के अन्य पहलुओं पर काम करने का दावा भी करती रही है। सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिये केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा मिलकर काम करने की ज़रूरत भी बतलाई गई है। मंत्रालय ने कई अन्य संबंधित संगठनों के साथ मिलकर इन्हें रोकने की ठानी है। इस कार्यक्रम को 4ई का नाम दिया गया हैए जिसमें शिक्षा ;एजूकेशनद्धए इंजीनियरिंग ;सड़क और वाहन दोनोंद्धए प्रवर्तन ;एनफोर्समेंटद्ध और आपातकालीन देखभाल ;इमरजेंसी केयरद्ध शामिल हैं। मंत्रालय का यह भी दावा है कि वह सड़क सुरक्षा ऑडिट कराने जा रही है। इस क्षेत्र में कई तरह के शोधए अध्ययन आदि भी किये जा रहे हैं ताकि सड़कों को पूर्णतरू निरापद बनाया जा सके। यह रिपोर्ट बहुत ही चेतावनी भरी है। इसलिये सरकार को चाहिये कि वह सभी आवश्यक कदम उठाये। देखा तो यह जाता है कि सरकारों की रुचि केवल सड़कों के अनावश्यक रूप से चौड़ीकरण और फोर लेन या सिक्स लेन बनाने में रहती हैं। ये सड़कें परिवहन का समय घटाने और हादसों को रोकने के नाम पर चौड़ी तो कर दी जाती हैं लेकिन दुर्घटनाओं में कोई कमी नहीं हो पाती। सफर में लगने वाला वक्त ज़रूर घट जाता है परन्तु वह इकलौता लाभ पर्याप्त नहीं है। देखा यह भी गया है कि वाहन चलाने वाले और रास्तों पर चलने वाले कोई भी सुरक्षित नहीं है। यहां तक कि रास्तों के किनारे रहने वाले भी दुर्घटनाओं की आशंका में जीते हैं।

दिल्ली के मुख्यमंत्री के बाद ईडी की नजर अब केरल पर

पी. श्रीकुमारन

थॉमस इसाक को इसलिए निशाना बनाया जा रहा है क्योंकि वह केरल इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बोर्ड ;केआईआईएफबीद्ध फंड द्वारा मसाला बांड के मुद्दे की जांच के संबंध में उन्हें श्ठीकश् करने के ईडी के प्रयासों का सफलतापूर्वक विरोध कर रहे हैं। ईडी इसहाक को एक के बाद एक समन जारी करने में व्यस्त है और वह बार.बार इससे पल्ला झाड़ रहे हैं। केरल के पूर्व वित्त मंत्री ने समन को अवैध और मनमाना बताते हुए ईडी के कदम का विरोध किया था। प्रवर्तन निदेशालयए दिल्ली के मु यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिर तारी और आप के अन्य नेताओं के खिलाफ अपनी कार्रवाई के बादए जिसे वह एक श्सफलश् अभियान मानता हैए ने अब केरल पर अपनी नजरें गड़ा दी हैं।

लेकिन केंद्रीय जांच एजंसी को पता होना चाहिए कि केरल एक अलग चाय का प्याला है। उत्तर भारतीय राज्य में उसने जो रणनीति सफलतापूर्वक अपनाई है वह केरलए तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में नहीं चलेगी।

एजंसी ने केरल के खिलाफ अपने अभियान में जो नवीनतम कदम उठाया हैए वह मु यमंत्री पिनाराई विजयन की बेटी टीण् वीणा की कंपनी से जुड़े कथित मासिक भुगतान विवाद के संबंध में जांच रिपोर्ट ;ईसीआईआरद्ध दर्ज करना है। ईसीआईआरएजंसी की कोच्चि इकाई द्वारा धन शोधन निवारण अधिनियम ;पीएमएलएद्धए 2002 के तहत दायर किया गया है।

यह कार्रवाई अगस्त 2003 में आयकर अंतरिम निपटान बोर्ड ;आईटीएसआईबीद्ध की एक रिपोर्ट के आधार पर की गई है जिसमें कहा गया था कि उनकी कंपनीए एक्सालॉजिक सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड को कोच्चि स्थित कोचीन मिनरल्स एंड रूटाइल लिमिटेड से मासिक भुगतान के रूप में 1ण्72 करोड़ रुपये मिले थे। सीएमआरएलए हालांकि बदले में दी गई किसी भी सेवा का कोई सुबूत नहीं था। मासिक भुगतान मामले में कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के तहत गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय ;एसआईएफओद्ध द्वारा जांच चल रही है।

वीणा के अलावाए सीएमआरएल और केरल राज्य औद्योगिक विकास निगम ;केएसआईडीसीद्ध की भूमिका की भी जांच की जा रही हैए जिसके पास सीएमआरएल में 13ण्4 प्रतिशत शेयर हैं। यह उल्लेख किया जा सकता है कि फरवरी में कर्नाटक उच्च न्यायालय ने कंपनी के मामलों में एसएफआईओ द्वारा जांच का आदेश देने में कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ;एमसीएद्ध की कार्रवाई को चुनौती देने वाली एक्सालॉजिक द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया था।

ईडी का नवीनतम कदम एलडीएफ सरकार को अस्थिर करने के लिए केंद्र सरकार के आदेश पर उसके पिछले प्रयासों की निराशाजनक विफलता की पृष्ठभूमि में आया है। न केवल इस तरह के दुस्साहस विफल हो गयेए बल्कि लोगों ने सीपीआई ;एमद्ध के नेतृत्व वाले एलडीएफ को 2021 के राज्य विधानसभा चुनावों में बड़े बहुमत के साथ सत्ता में वापस लाकर एलडीएफ सरकार के खिलाफ भाजपा और कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिकफ्रंट ;यूडीएफद्ध के अभियान का करारा जवाब दिया। निन्दा का अभियान स्पष्ट रूप से मतदान के रुझान पर कोई प्रभाव डालने में विफल रहा।

मु यमंत्री की बेटी और सीपीआई ;एमद्ध केंद्रीय समिति के सदस्य थॉमस इसाक के खिलाफ ईडी के नवीनतम कदम का समय महत्वपूर्ण है क्योंकि यह लोकसभा चुनाव से ठीक पहले हो रहा है। यह और कुछ नहीं बल्कि घबराई हुई मोदी सरकार का एक हताश कदम हैए जो चुनावी बांड मामले में हुए खुलासों के प्रतिकूल प्रभाव से जूझ रही है। लोगों का ध्यान मुद्दे से भटकाने के लिए ही झारखंड के मु यमंत्री हेमंत सोरेन और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिर तारी की गई है। भगवा खेमा स्पष्ट रूप से सोचता है कि इस तरह के कदमों से उसे भरपूर चुनावी लाभ मिलेगा। लेकिन अगर वह ऐसा सोचता है तो यह आत्मसंतुष्टि की झूठी भावना में खोना होगा। कुछ भी होए इस दुस्साहस का संघ परिवार और मोदी सरकार पर बुरा प्रभाव पड़ने वाला है। संकेत पहले से ही मौजूद हैं।

भाजपा.आरएसएस कबीला इतना डरा हुआ क्यों हैघ् कारण स्पष्ट हैं। नागरिक संशोधन कानून ;सीएएद्ध और चुनावी बांड मुद्दे के खिलाफ वामपंथी दलों द्वारा चलाया जा रहा अभियान लोगों के मन में बड़ा प्रभाव पैदा कर रहा है। वाम दल निस्संदेह लाभप्रद स्थिति में हैं क्योंकि वे एकमात्र ऐसे दल हैं जिन्होंने चुनावी बांड नहीं लिया है। यह सीपीआई ;एमद्ध थी जिसने चुनावी बांड के खिलाफ शीर्ष अदालत का रुख किया और एक अनुकूल फैसला जीताए जिसने मोदी सरकार की विश्वसनीयता को एक विनाशकारी झटका दिया है।

यह विशेष रूप से वाम दलों के खिलाफ आक्रामक अभियान की व्या या करता हैए और वीणा को निशाना बनाया गया है क्योंकि वह पिनाराई विजयन की बेटी हैं जो केंद्र सरकार और भाजपा.आरएसएस जोड़ी के खिलाफ अभियान चला रहे हैं। केरल के मु यमंत्री अपनी चुनावी रैलियों में सीएए मुद्दे और चुनावी बांड मामले का प्रभावी ढंग से उपयोग कर रहे हैंए जो भगवा खेमे में निराशा उत्पन्न करते हुए भारी भीड़ को आकर्षित कर रहा है। थॉमस इसाक को इसलिए निशाना बनाया जा रहा है क्योंकि वह केरल इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बोर्ड ;केआईआईएफबीद्ध फंड द्वारा मसाला बांड के मुद्दे की जांच के संबंध में उन्हें श्ठीकश् करने के ईडी के प्रयासों का सफलतापूर्वक विरोध कर रहे हैं। ईडी इसहाक को एक के बाद एक समन जारी करने में व्यस्त है और वह बार.बार इससे पल्ला झाड़ रहे हैं। केरल के पूर्व वित्त मंत्री ने समन को अवैध और मनमाना बताते हुए ईडी के कदम का विरोध किया था। अपनी ओर सेए केरल के मु यमंत्री ने केंद्र सरकार पर विपक्षी दलों को डराने.धमकाने के लिए केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करने का आरोप लगाते हुए कड़ी आलोचना की है। उन्होंने अपने दिल्ली समकक्ष अरविंद केजरीवाल की गिर तारी का भी जिक्र करते हुए कहा कि इसे पहली या आखिरी गिर तारी नहीं माना जा सकता। लोकतंत्र खतरे में है और समय की मांग है कि हम अपनी पूरी ताकत से इसकी रक्षा करें। सीपीआई ;एमद्ध नेता एकजुट हो गये हैं और केरल के मु यमंत्री को पूर्ण समर्थन मिल रहा है।

अपनी कड़ी प्रतिक्रिया मेंए सीपीआई ;एमद्ध के राज्य सचिव एमवी गोविंदन ने कहा कि ईडी का कदम केरल में विपक्ष के नेता वीडी सतीसन की मदद करने के लिए हैए जो पिनाराई के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। गोविंदन ने कहाए ईडी भाजपा के राजनीतिक एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए विपक्षी नेताओं के खिलाफ मामले दर्ज कर रही है। पिछले विधानसभा चुनाव में भी केंद्र सरकार ने ईडी और अन्य जांच एजेंसियों का इस्तेमाल किया था। गोविंदन ने गैर.भाजपा नेताओं के खिलाफ ईडी की छापेमारी पर कांग्रेस की आलोचना की। उन्होंने कहा कि पार्टी तभी प्रतिक्रिया देती है जब ईडी कांग्रेस नेताओं के पीछे जाती है।

एक बात की भविष्यवाणी निश्चितता के साथ की जा सकती है। एलडीएफ सरकार के खिलाफ ईडी की ओर से किसी भी दुस्साहस का भगवा खेमे और केंद्र सरकार पर बुरा असर पड़ना तय है। केरल में एलडीएफ के लिए बढ़ते समर्थन ने स्पष्ट रूप से भाजपा.आरएसएस कबीले को परेशान कर दिया है। इसलिए यह पिनाराई सरकार को किसी भी तरह से अस्थिर करने का प्रयास कर रहा है। लेकिन केरल के प्रबुद्ध लोग पूरी तरह से एलडीएफ सरकार और मु यमंत्री के पीछे हैं क्योंकि उन्हें एहसास हो गया है कि वह लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई में आगे आकर नेतृत्व कर रहे हैं और सुनिश्चित कर रहे हैं कि लोकतांत्रिकए धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी भारत का विचार बरकरार रहे।

बहुसंख्यकवादी नैरेटिव को टेका लगाती फिल्में–स्वातंर्त्य वीर सावरकर

राम पुनियानी

बहुसं यकवादी और विघटनकारी मुद्दों पर आधारित राजनीति और हिन्दू राष्ट्रवादी विचारधारा का बोलबाला बढ़ने के साथ ही भारत की फ़िल्मी दुनिया के कई लोग ऐसी फिल्में बनाने लगे हैं जो एक विशिष्ट विघटनकारी नैरेटिव को प्रोत्साहित करती हैं और राजनीति और इतिहास को देखने के सांप्रदायिक नज़रिए पर आधारित हैं।

फिल्म जनसंचार का एक शक्तिशाली माध्यम है जो सामाजिक समझ को कई तरह से प्रभावित करता है। कई दशकों पहले भारत में ऐसी फिल्में बनीं जो सामाजिक यथार्थ को प्रतिबिंबित करती थीं और प्रगतिशील मूल्यों को बढ़ावा देती थीं. श्मदर इंडियाश्ए श्दो बीघा ज़मीनश् और श्नया दौरश् ऐसी ही कुछ फिल्में थीं। कुछ बायोपिक फिल्मों ने भी यथार्थपरक आम समझ को विस्तार और समावेशी मूल्यों को प्रोत्साहन दियाण् रिचर्ड एटनबरो की गांधी और भगत सिंह के जीवन पर बनी कुछ फिल्में अत्यंत प्रेरणास्पद थीं। ये बायोपिक मेहनत और सावधानी से किए गए शोध पर आधारित थीं और अपने.अपने नायकों के वास्तविक चरित्र को परदे पर उकेरती थीं।

बहुसं यकवादी और विघटनकारी मुद्दों पर आधारित राजनीति और हिन्दू राष्ट्रवादी विचारधारा का बोलबाला बढ़ने के साथ ही भारत की फ़िल्मी दुनिया के कई लोग ऐसी फिल्में बनाने लगे हैं जो एक विशिष्ट विघटनकारी नैरेटिव को प्रोत्साहित करती हैं और राजनीति और इतिहास को देखने के सांप्रदायिक नज़रिए पर आधारित हैं। ऐसी सभी फिल्मों में सच को तोड़ा.मरोड़ा जाता है और ज्यादातर मामलों में हिन्दू राष्ट्रवादी नायकों का महिमामंडन किया जाता है। इनमें से अधिकांश फिल्मों में सच के साथ समझौता किया जाता है और झूठ को सच के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। ऐसी ही एक फिल्म श्द कश्मीर फाईल्सश् का प्रधानमंत्री मोदी और संघ प्रमुख मोहन भागवत ने जमकर प्रचार किया था। भाजपा के कई नेताओं ने थोक में इस फिल्म के टिकट खरीदकर अपने इलाके के लोगों को बांटे थे ताकि वे फिल्म देख सकें। इस फिल्म का प्रचार करने वालों का दावा था कि यह फिल्म कश्मीर का असली सच लोगों के सामने लाई है।

इसी तरह की एक दूसरी फिल्म श्द केरेला स्टोरीश् में इस्लाम में धर्म परिवर्तन करने वालों और इस्लामिक स्टेट ;आईएसद्ध में शामिल होने वालों की सं या को बहुत बढ़ा.चढ़ाकर बताया गया था। इस तरह की कई फिल्में बॉक्स आफिस पर बुरी तरह पिट गईं। इनमें शामिल थीं श्72 हूरेंश् जिसमें आतंकवाद को राजनीति की बजाय धर्म से जोड़ा गया था। इस फिल्म में इस तथ्य को भी दबाया गया था कि हिन्दू धर्म में भी स्वर्ग में अप्सराओं के साथ आनंद करने की बातें कही गई हैं। इसी तरह अन्य धर्मों में भी स्वर्ग में परियों की चर्चा है।

श्द केरेला स्टोरी, द कश्मीर फाईल्स, 72 हूरें इत्यादि का उद्देश्य है इस्लामोफोबिया फैलाना। दूसरी ओर गोडसे पर 2022 में बनी फिल्म में महात्मा गांधी के हत्यारे का महिमागान किया गया था। इसमें संघ परिवार का वह पुराना झूठ फिर एक बार दुहराया गया था कि गांधीजी ने भगत सिंह को फांसी से नहीं बचाया और उनकी शहादत पर शोक व्यक्त करने वाले कांग्रेस के एक प्रस्ताव का विरोध किया। और अब आई है रणदीप हुड्डा की श्स्वातंर्त्यवीर सावरकरश्। यह झूठ का प्रचार करने में नई ऊंचाईयां अर्जित करती है। फिल्म में दिखाया गया है कि भगत सिंह सावरकर से जा कर मिले और यह इच्छा व्यक्त की कि वे सावरकर की पुस्तक श्फर्स्ट वॉर ऑफ़इंडीपेंडेंसश् का मराठी से अंग्रेजी में अनुवाद करना चाहते हैं!

सच क्या हैघ् कई क्रांतिकारियों ने इस पुस्तक को पढ़ा है और उसे सराहा भी है। मगर समस्या यह है कि यह पुस्तक मराठी में 1908 के आसपास प्रकाशित हुई थी और इसके एक साल बाद उसका अंग्रेजी अनुवाद प्रकाशित हो गया था। भगत सिंह का जन्म 1907 में हुआ था और वे अपने जीवन में कभी सावरकर से नहीं मिले।

फिल्म में सावरकर को यह कहते हुए दिखाया गया है कि भारत 1912 तक स्वाधीनता हासिल कर लेगा . अर्थात जब हमें स्वतंत्रता मिली उस से करीब 35 साल पहले। सच यह है कि 1910 से ही सावरकर अंडमान के सेल्युलर जेल में थे और वहां से अंग्रेज सरकार से माफी मांगते हुए याचिकाएं लिख रहे थेण् सन् 1912 तक वे ऐसी तीन याचिकाएं लिख चुके थे। इन सभी याचिकाओं में सरकार से उसका विरोध करने के लिए क्षमायाचना की गई थी और यह भी कहा गया था कि अगर उन्हें जेल से रिहा कर दिया जाए तो वे निष्ठापूर्वक ब्रिटिश सरकार के प्रति वफादार रहेंगे। और जेल से रिहा होने के बाद सावरकर ब्रिटिश सरकार के प्रति वफादार बने रहे। हमारे स्वाधीनता संग्राम ने 1920 में जोर पकड़ा जब कांग्रेस द्वारा शुरू किए गए असहयोग आंदोलन में बड़ी सं या में लोगों ने भागीदारी की।

फिल्म यह प्रश्न भी उठाती है कि किसी कांग्रेस के नेता को अंडमान जेल क्यों नहीं भेजा गया और क्यों उन्हें भारत के जेलों में रखा गया। पहली बात तो यह है कि इस तथ्य की सत्यता की पुष्टि की जानी होगी। दूसरी बात यह कि सन् 1920 के बाद से कांग्रेस और गांधीजी ने अहिंसा की राह अपना ली थी और इस कारण उनके अनुयायियों को अंडमान या फांसी की सजा नहीं दी गई और उन्हें भारतीय जेलों में ही रखा गया। भगत सिंहए राजगुरू और सुखदेव को हिंसा में शामिल होने के कारण फांसी की सजा दी गई थी। चूंकि गांधीजी के नेतृत्व में कांग्रेस ने अहिंसा के सिद्धांत का पालन किया इसलिए उसके सदस्यों को फांसी या अंडमान की सजा नहीं हुई। यह फिल्म हमें बताती है कि भारत को अहिंसा के रास्ते नहीं वरन हिंसा के रास्ते स्वतंत्रता मिली। भारत में जो क्रांतिकारी सक्रिय थे उनमें से अधिकांश हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन से थे। भगत सिंह और उनके साथियों की मृत्यु के बाद भारत में कोई बड़ा क्रांतिकारी आंदोलन नहीं हुआ। सावरकर के अभिनव भारत ने सावरकर द्वारा सरकार से क्षमायाचना करने के बाद ब्रिटिश सरकार का विरोध करना बंद कर दिया। सुभाषचन्द्र बोसए जिन्होंने आजाद हिंद फौज का गठन किया थाए 1945 में मारे गए और आजाद हिंद फौज के अफसरों और सिपाहियों को लालकिले में बंदी बनाकर रखा गया। अदालतों में इन युद्धबंदियों का बचाव करने के लिए जवाहर लाल नेहरू की पहल पर कांग्रेस ने एक समिति का गठन किया था।

फिल्म यह भी बताती है कि आजाद हिंद फौज का गठन कर अंग्रेजों से लड़ने की सलाह सावरकर ने ही बोस को दी थी! यह तथ्यों के एकदम विपरीत है। कांग्रेस छोड़ने के बाद ही बोस ने यह तय कर लिया था कि वे जर्मनी और जापान की मदद से ब्रिटिश सरकार के विरूद्ध जंग छेड़ेंगे। जिस समय बोस ब्रिटिश सरकार के विरूद्ध युद्धरत थे उस समय सावरकर हिंदू महासभा से यह अनुरोध कर रहे थे कि वह अधिक से अधिक सं या में हिंदुओं को ब्रिटिश सेना में भर्ती करवाए ताकि द्वितीय विश्वयुद्ध में ब्रिटेन की शक्ति बढ़े।

हिन्दू महासभा के कलकत्ता अधिवेशन को संबोधित करते हुए सावरकर ने सभी विश्वविद्यालयोंए महाविद्यालयों और विद्यालयों से यह अपील की थी कि वे किसी भी तरह और हर तरह से यह प्रयास करें कि भारतीय युवा ब्रिटिश सेना में भर्ती हों। इसके अगले साल 1940 में गांधीजी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया। उसी साल दिसंबर में हिंदू महासभा के सत्र को संबोधित करते हुए सावरकर ने हिंदू युवकों का आह्वान किया कि वे बड़े पैमाने पर ब्रिटिश सेना की विभिन्न शाखाओं में भर्ती हों। सावरकर के बारे में लिखते हुए सुभाषचन्द्र बोस ने कहा थाए श्ऐसा प्रतीत होता है कि सावरकर अंतरराष्ट्रीय स्थिति से नावाकिफहैं और केवल यह सोच रहे हैं कि ब्रिटिश सेना में भर्ती होने से हिंदुओं को सैन्य प्रशिक्षण हासिल हो सकेगा।श् बोस का निष्कर्ष था कि श्मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा से कोई अपेक्षा नहीं की जा सकती।श

आजाद हिंद रेडियो के जरिए भारतीयों को संबोधित करते हुए सुभाषचन्द्र बोस ने कहा थाए श्मैं मिस्टर जिन्नाए मिस्टर सावरकर और अन्य ऐसे सभी लोगोंए जो अब भी ब्रिटिश सरकार के साथ समझौते की बात कर रहे हैंए से यह अनुरोध करना चाहता हूं कि वे यह समझ लें कि आने वाली दुनिया में ब्रिटिश साम्राज्य नहीं होगाश।जहां तक फिल्म में सावरकर और सुभाषचंद्र बोस को सहयोगियों की तरह प्रस्तुत करने का प्रश्न हैए नेताजी के प्रपौत्र चन्द्रकुमार बोस ने फिल्म का ट्रेलर देखने के बाद हुड्डा से कहा थाए श्कृपया नेताजी को सावरकर से मत जोड़िएण् नेताजी एक समावेशी और धर्मनिरपेक्ष नेता थे। वे देशभक्तों के देशभक्त थेश।

यह फिल्म आने वाले चुनावों के मद्देनजर हिंदू राष्ट्रवादी राजनीति को मजबूती देने के लिए सच को तोड़ने.मरोड़ने का एक और प्रयास है।

Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at: http://www.software602.com/

विविध समाचार

सिदगोड़ा में पड़ोसियों ने घर में घुस की मारपीट.तोड़फोड़

जमशेदपुर ०९/०४ (संवाददाता): सिदगोड़ा थाना क्षेत्र के भुइयांडीह लाल भट्टा निवासी उमेश यादव व उनके परिजनों के साथ सोमवार की सुबह मारपीट की गई। उमेश के अलावा पत्नी राजामणी देवीए पुत्र पप्पू यादवए बेटी पूजा व पुष्पा कुमारी के साथ मारपीट की। उमेश ने पड़ोसी मुन्ना यादवए नरेश यादवए प्रदीप यादव समेत अन्य पर घर में घुस मारपीट का आरोप लगाया है। घायलों को एमजीएम लाया गया। मामले की शिकायत थाना में भी की है। उमेश ने बताया. अतिक्रमण का विरोध करने पर पड़ोसियों ने घर में घुस मेरे परिवार के लोगों के साथ मारपीट की। उमेश ने आरोप लगाया कि सभी लाठी.डंडा लेकर घर में घुसे थे।

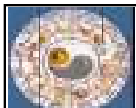

आज का राशिफल

मेष - आज के दिन धार्मिक और आध्यात्मिक प्रवृत्तियाँ विशेष रहेंगी। मन में द्विधा रहने से ठोस निर्णय नहीं ले सकेंगे। पैसे की लेन-देन या आर्थिक व्यवहार न करने की गणेशजी की सलाह है।

वृषभ - गणेशजी कहते हैं कि व्यापार में वृद्धि होने के साथ व्यापार के स बंध में सौदे लाभदायक साबित होंगे। आय के साधनों में वृद्धि होगी। बुजुर्गों तथा मित्र मंडल से लाभ और सुखद क्षणों का अनुभव मिलेगा।

मिथुन - शारीरिक और मानसिक सुख बने रहेंगे। नौकरी - व्यवसाय में आपके परिश्रम का मुआवजा मिलता हुआ प्रतीत होगा। अधिकारी वर्ग के प्रोत्साहन से आपका उत्साह बढ़ेगा। सामाजिक क्षेत्र में प्रतिष्ठा बढ़ेगी।

कर्क - गणेशजी कहते हैं कि आज आपकी भाग्य वृद्धि के साथ आकस्मिक धन लाभ होगा। विदेश जाने के इच्छुक लोगों के प्रयास सफल होंगे। तथा विदेश से अच्छे समाचार आएँगे।

सिंह - आज आपको स्वास्थ्य का ध्यान रखना रहेगा। तबीयत के पीछे धन खर्च होने की संभावना है। निषेधात्मक विचार आपको गलत मार्ग पर न ले जाए, उसका ध्यान रखने के लिए गणेशजी कहते हैं।

कन्या - गणेशजी की कृपा से दांपत्यजीवन के सुखद क्षणों का अनुभव करेंगे। सामाजिक और सार्वजनिक क्षेत्र में आप याति और प्रतिष्ठा प्राप्त करेंगे। मनोरंजन की प्रवृत्तियों में भाग लेंगे। वस्त्राभूषण और वाहन की खरीदी होगी।

तुला - गणेशजी कहते हैं कि सामान्ज रूप से आज स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और बीमार व्यक्ति के भी तबीयत में सुधार होगा। घर में सुख- शांति के वातावरण में आप समय व्यतीत करेंगे। कार्य में सफलता और यश मिलने से उत्साह बढ़ेगा।

वृश्चिक - आज यात्रा प्रवास का आयोजन न करने की सलाह गणेशजी देते हैं। स्वास्थ्य के स बंध में चिंतित रहेंगे। संतानों के स बंध में समस्याएँ खड़ी होंगी। स्वाभिमान भंग न हो इसका ध्यान रखें।

धनु - गणेशजी कहते हैं कि आज आपको अत्यधिक संवेदनशीलता के कारण और घरेलू मामलों को लेकर मानसिक तनाव खड़े होने की संभावना है। मन में उठनेवाली द्विधाओं से आप मानसिक उचाट अनुभव करेंगे।

मकर - आज आप रणनीति में शत्रुओं को परास्त करेंगे। नए कार्यों के आरंभ के लिए तैयार रहें। सफलता मिलेगी। आप हरेक कार्य तन-मन से स्वस्थ रहकर करेंगे। व्यापार-धंधे में लाभ होगा।

कुंभ - गणेशजी बताते हैं कि मन में द्विधाएँ खड़ी होने से आप कोई ठोस निर्णय पर नहीं पहुँच सकेंगे। महत्त्वपूर्ण निर्णय न लें। वाणी पर संयम नहीं रहनेसे पारिवारिक सदस्यों के साथ मनमुटाव होने की संभावना है।

मीन - आनंद- उत्साह और तन-मन की प्रसन्नता आपके दिन में चेतना और स्फूर्ति का संचार करेंगे। नए कार्य हाथ में लेंगे तो उसमें सफलता मिलेगी। धार्मिक मांगलिक प्रसंगों में जाएँगे।

पलामू पुलिस ने कोढ़ा गैंग के 5 अपराधियों को पकड़ा

पलामू ०९/०४ (संवाददाता): झारखंड के पलामू जिले की पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने कोढ़ा गैंग के 3 अपराधियों को गिर तार किया है। इनकी मदद करने के आरोप में 2 स्थानीय लोगों को हिरासत में लिया गया है। पकड़े गए अपराधियों में से 2 बिहार के रहने वाले हैं। वहीं 1 अपराधी छत्तीसगढ़ का रहने वाला है। स्थानीय लोगों में 1 महिला और 1 पुरुष हैं। यह सभी बिहार के कटिहार के कोढ़ा गांव के रहने वाले गिरोह के सरगना वासुदेव नट के लिए काम करते थे। पुलिस ने इनके पास से 2 फर्जी नंबर प्लेट लगी बाइक तथा 37 पुड़िया खुजली का पाउडर बरामद किया है। पुलिस अधीक्षक पलामू चंदन कुमार सिन्हा ने बताया कि पकड़े गए अपराधियों में से एक कोढ़ा गैंग के सरगना वासुदेव नट का दामाद है। गिरोह का सरगना लूट की घटनाओं के लिए बिहार तथा छत्तीसगढ़ से अपराधियों तथा अपने रिश्तेदारों को बुलाता है। यह सभी लोग अलग.अलग जिलों में रहकर पहले रेकी करते हैं। इसके आधार पर घटनाओं को अंजाम देते हैं। पलामू में भी इसी पैटर्न पर काम चल रहा था। इस काम में 2 स्थानीय लोग इनकी मदद कर रही थे। गिरोह के सरगना का इन लोगों के यहां लगातार आना.जाना लगा रहता था। बताया गया कि इस गिरोह के लोग बैंक से रुपए निकाल कर जाने वालों का पीछा करते है। इसके बाद अपने साथियों के सहयोग से उसका रुपया छीन लेते है। इसमें रेकी करनेए पीछा करने एवं खुजली पाउडर डालने वाला टीम 1 बाइक पर तथा रुपये की छिनतई करने वाली टीम दूसरे बाइक पर रहती है। घटना के समय आपस में बातचीत करने के लिए सभी लोग फर्जी सिमकार्ड का इस्तेमाल करते है। वारदात को अंजाम देने के बाद मोबाइल को बंद कर देते हैं। घटना में प्रयुक्त बाइक बिहार से चोरी कर लाई जाती है। पलामू में दिसंबर माह में एक के बाद एक दो वारदातों को अंजाम दिया गया। ब्ब्न्टकी मदद से पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। इसमें यह अपराधी पुलिस के हत्थे चढ़ गए। पकड़े गए तीनों अपराधी 1 माह पहले ही पलामू आए थे।

पीएम आवास नहीं बनाने वाले 400 लोगों को नोटिस

बसिया ०९/०४ (संवाददाता): बसिया के प्रखंड विकास पदाधिकारी रविन्द्र कुमार गुप्ता ने प्रधानमंत्री आवास के 400 लाभुकों को कार्रवाई के लिए नोटिस भेज दिया गया है। इस संबंध में प्रखंड विकास पदाधिकारी ने कहा कि वर्ष 2016 से 2021 तक के प्रधानमंत्री आवास के कुछ लाभुकों द्वारा बार.बार मकान बनाने के लिए कहने के बाद भी आवास बनाने की ओर कोई ध्यान नहीं है।ऐसे लाभुकों को एक मौका देकर प्रधानमंत्री आवास बनाने को कहा जा रहा हैए जिसे कुछ लोगों द्वारा आवास बनाया जा रहा किंतु कुछ लाभुकों को आवास निर्माण से कोई मतलब नहीं दिखाई दे रहा है। वैसे लाभुकों को नोटिस भेजकर आगाह किया गया। साथ ही सरकारी कर्मियों को भी आवास पूर्ण करने में लगाया गया है। इसके बाद कानूनी प्रक्रिया तहत राशि वापस कराए जायंगे।

एचईसी को बचाने के लिए गैर भाजपाई सांसदों का दल प्रधानमंत्री से मिलेगा

रांची ०९/०४ (संवाददाता): एचईसीकर्मियों के बकाया वेतन भुगतान के संबंध में प्रबंधन ने अब तक कोई ठोस निर्णय नहीं लिया है। इससे आक्रोशित कामगारों ने आंदोलन तेज करने का निर्णय लिया है। इसे लेकर गुरुवार को एचईसी बचाओ मजदूर जनसंघर्ष समिति की महत्वपूर्ण बैठक समिति के मु य संरक्षक व पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय के एचईसी परिसर स्थित आवासीय कार्यालय पर हुई। अध्यक्षता खिजरी के विधायक राजेश कच्छप ने की। इसमें सुबोधकांत सहाय ने सभी वामपंथी दलों और गैर भाजपाई राजनीतिक दलों के सांसदों का आह्वान करते हुए कहा कि दिल्ली में एक प्रतिनिधिमंडल एचईसी को बचाने को लेकर प्रधानमंत्री और उद्योग मंत्री से मिलकर वार्ता करें। उन्होंने कहा कि दिल्ली में कैबिनेट सचिव से एचईसी को बचाने के संबंध में शुक्रवार को वार्ता की जाएगी।

एचईस प्रबंधन ने सर्कुलर जारी कर कहा है कि निगम के सभी संयंत्र व कार्यालय की वास्तविक सं या के कम से कम 50 प्रतिशत के साथ प्रतिदिन चलेंगे। यह प्रावधान कोविड के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए लागू किया गया है। ये तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। 37वें दिन भी जारी रही स्ट्राइक रू कामगारों का टूल डाउन स्ट्राइक गुरुवार को 37वें दिन भी जारी रही। रोज की तरह कामगार अपने.अपने प्लांट में उपस्थिति दर्ज किए और फिर प्रबंधन के खिलाफ रोष जाहिर करते हुए अपने बकाए वेतन की मांग करते हुए नारे लगाए। इन 37 दिनों के टूल.डाउन स्ट्राइक में एचईसी को अबतक करीब 35 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है।एचईसी को बचाने के लिए गुरुवार को दिल्ली रवाना हो गए। सहाय दिल्ली में केंद्रीय कैबिनेट सचिव से मिलेंगे। इससे पहले अपने आवासीय कार्यालय में हुई यूनियनों व अन्य संगठनों की बैठक में उन्होंने कहा कि मोदी सरकार की जनविरोधी नीतियों के कारण एचईसी पर बंदी की तलवार लटक रही है। एशिया प्रसिद्ध कारखाना बचाने के लिए सभी गैर भाजपाई राजनीतिक दलोंए सामाजिक संस्थाओं और श्रमिक संगठनों को अब आर.पार की लड़ाई लड़नी होगी

वेंडिंग कमेटी ने 144 दुकानदारों की सूची खारिज की, फिर से होगा सत्यापन

रांची ०९/०४ (संवाददाता): नागाबाबा खटाल वेजिटेबल मार्केट में जगह आवंटन का मामला फिर फंस गया हैए क्योंकि नगर निगम ने गुरुवार को मार्केट में जगह आवंटन के लिए पहली बार टाउन वेंडिंग कमेटी की बैठक बुलाई थी। जिसमें निगम की ओर से 144 सब्जी विक्रेताओं की सूची स्वीकृति के लिए रखी गईए पर टाउन वेंडिंग कमेटी के सदस्यों ने उसे खारिज कर दिया।कमेटी के सदस्य नागेंद्र पांडेय ने कहा कि वर्ष 2016 में जो सर्वे स मान फाउंडेशन ने किया थाए वह सही नहीं है। इसलिएए उसके आधार पर जगह का आवंटन करना गलत होगा। नए सिरे से सर्वे करने के बाद ही जगह आवंटित की जाए। इस पर डिप्टी मेयर संजीव विजयवर्गीय ने निगम के अफसरों को कहा कि दुबारा सर्वे करके वर्ष 2016 की सर्वे सूची में शामिल सब्जी विक्रेताओं का जल्द सत्यापन करेंए ताकि पारदर्शी तरीके से जगह का आवंटन हो सके। टीवीसी सदस्यों ने कहा कि गोपनीय तरीके से तीन बार सभी सब्जी.फल विक्रेताओं की वीडियोग्राफी कराई जाए। इसके बाद वर्षों से जो भी दुकानदार सब्जी बेच रहे हैंए उनका सत्यापन कर जगह आवंटित करें।डिप्टी मेयर संजीव विजयवर्गीय ने कचहरी चौक से सर्जना चौक तक रोड के दोनों किनारे दुकान लगाने वालों पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया।

स्कूली शिक्षा विभाग मोरहाबादी में उस जमीन पर बनाने जा रहा राज्य का सबसे बड़ा पुस्तकालय, जिस पर दो विवि कर रहे दावेदारी

रांची ०९/०४ (संवाददाता): स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग मोरहाबादी कैंपस में राज्य की सबसे बड़ी लाइब्रेरी के लिए अत्याधुनिक बिल्डिंग का निर्माण कराएगा। पांच तल्ले में विश्वस्तरीय सुविधाएं होंगी। इधरए स्कूली शिक्षा विभाग जिस जमीन पर लाइब्रेरी का निर्माण कराने की तैयारी कर रहा हैए उस पर आरयू और डॉण् श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी डीएसपीएमयू दोनों शुरू से अपनी दावेदारी जताते रहे हैं। डीएसपीएमयू प्रशासन ने निर्माण का विरोध करने का निर्णय लिया है। बताते चलें कि दो एकड़ भूमि पर बननेवाली लाइब्रेरी बिल्डिंग का डीपीआर तैयार कर लिया गया है। नई लाइब्रेरी में 5000 छात्रों के बैठने की क्षमता होगीए लेकिन डीएसपीएमयू के रुख को देखते हुए बाधा उत्पन्न होने की आशंका बढ़ गई है। नई लाइब्रेरी में जेनरल रीडिंग रूमए पीरियडिकल रीडिंग रूम, स्पेशल रीडिंग रूम, रिसर्च, स्टॉक रूम, ग्रुप स्टडी रूम, सेमिनार रूम, कॉन्फ्रेंस रूम, रिसर्च क्यूबिकल, एग्जिबिशन रूमए डिप्टी लाइब्रेरी रूम, लाइब्रेरियन रूम, टेक्निकल स्टॉफरूमए एडमिनिस्ट्रेटिव स्टॉफ रूम, डिस्प्ले स्पेस एट एंट्रेंस, कैफेटेरिया, पार्किंग स्पेस समेत अन्य सुविधाएं शामिल हैं।

रांची में पहली बार नौवीं के बच्चों को मिलेगी साइकिल

रांची ०९/०४ (संवाददाता): झारखंड में पहली बार नौवीं के बच्चों को भी साइकिल दी जाएगी। इसके लिए रांची जिले के 10,410 बच्चों का चयन किया गया है। कोरोना के कारण पिछले साल साइकिल खरीदारी की राशि कल्याण विभाग की ओर से विद्यार्थियों के खाते में नहीं दी गई थी।

ऐसे में आठवीं कक्षा से पास होकर 2021 में नौंवी कक्षा में जाने वाले विद्यार्थियों को भी राज्य सरकार साइकिल उपलब्ध कराएगी। यह पहली बार है जब नौवीं कक्षा के विद्यार्थियों को साइकिल दी जाएगी। निरूशुल्क साइकिल वितरण योजना के तहत 10,410 स्टूडेंट्स को साइकिल मिलेगी। इसके तहत 5,827 छात्राओं और 4ए583 छात्रों को साइकिल मिलेगी।

वहीं इस बार रांची के सरकारी स्कूलों में आठवीं में पढ़ने वाले 30,493 विद्यार्थियों को साइकिल दी जाएगी। अनुसूचित जाति.जनजाति, अल्पसं यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की ओर से बच्चों को ये साइकिल दी जाएगी।

रांची में चयनित किए गए 30,493 विद्यार्थियों में 55 प्रतिशत साइकिल छात्राओं को मिलेगी। 16,736 छात्राओं को और 13,757 छात्रों को साइकिल मिलेगी। सबसे अधिक विद्यार्थी कांके प्रखंड के चयनित हुए हैं। यहां के 2,603 विद्यार्थियों को साइकिल मिलेगी। वहींए दूसरे नंबर पर बेड़ो प्रखंड के 2ए477 और अनगड़ा के 2,448 स्टूडेंट्स को साइकिल मिलेगी।

राज्य सरकार की निरूशुल्क साइकिल वितरण योजना का मु य उद्देश्य ड्रॉपआउट को रोकना है। खासकर गरीबी रेखा से नीचे जीवन गुजारने वाले एससी.एसटीए पिछड़ी जाति और अल्पसं यक वर्ग के बच्चों को आवागमन की सुविधा उपलब्ध कराना है। साधन की कमी से वे स्कूल जाना बंद न करें।

बूढ़ा की गिरफ् तारी पर बड़ी नक्सली घटना का अंदेशा

जमशेदपुर ०९/०४ (संवाददाता): कांड्रा के गिद्दीबेड़ा टोल प्लाजा के पास 12 नवंबर को नक्सलियों के सुप्रीम कमांडर किशन दा उर्फ बूढ़ा और उसकी पत्नी की गिर तारी के बाद नक्सली बड़ी घटना को अंजाम दे सकते हैं। इसी अंदेशा में एसएसपी डॉ एमण्तमिल वाणन ने पूर्वी सिंहभूम जिले के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में 28 जगहों पर फोर्स तैनात कर हाई अलर्ट रहने का निर्देश दिया है।सोमवार को नक्सल प्रभावित इलाकों के थानेदारों के लिए दिशा.निर्देश जारी किए। एसएसपी ने बताया. किशन दा की गिर तारी के बाद पटमदाए बोड़ामए घाटशिला और पश्चिम बंगाल से जुड़े इलाके काफी संवेदनशील हो गए हैं।

Printed, Published, Edited, & Owned by Prakash Kumar Dhal, Printed at Promodini Publication, Mainroad, Chhend colony, Rourkela-15 & Published at ECR-73, Chhend Colony, Rourkela-15, Editor : Prakash kumar Dhal, Email: kalingasamachar@gmail.com , Mob: 9439951525, Ph. 0661-2646999

Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at: http://www.software602.com/

ओडिशा समाचार

क्लिंग समाचार | राउरकेला, बुधवार 10 अप्रैल 2024 | पृष्ठ-6

भाजपा को झटका, लेखाश्री सामंतसिंघर ने पार्टी छोड़ बीजेडी का थामा हाथ

भुवनेश्वर। भाजपा को झटका देते हुए पार्टी की ओडिशा इकाई की उपाध्यक्ष लेखाश्री सामंतसिंघर ने इस्तीफा दे दिया है। लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनावों से पहले ये भाजपा के लिए बड़ा झटका है। लेखाश्री बीजू जनता दल ;बीजेडी में शामिल हो गई हैं।

लेखाश्री भृगु बक्सीपात्रा के बाद दूसरे भाजपा ओडिशा उपाध्यक्ष हैंए जिन्होंने चुनाव से कुछ सप्ताह पहले भाजपा से इस्तीफा दे दिया और बीजद में शामिल हो गईं। ओडिशा भाजपा अध्यक्ष मनमोहन सामल को लिखे अपने त्यागपत्र में लेखाश्री ने कहा कि नेतृत्व का विश्वास जीतने में नाकाम होने के कारण उन्होंने भाजपा छोड़ने का फैसला किया।

लेखाश्री ने कहा कि मैंने पिछले दस वर्षों से भारतीय जनता पार्टी में अपना खून.पसीना बहाया है। हालांकिए पूरी ईमानदारी और कड़ी मेहनत के बावजूदए मैं नेतृत्व का विश्वास हासिल नहीं कर सकी। इसलिएए मुझे लगता है कि मेरे पास करने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। इसके कारण ओडिशा के लोगों की सेवा करने की मेरी इच्छा पूरी नहीं हो रही है।

लेखाश्री पार्टी सांसद मानस मंगराज और सस्मित पात्रा की मौजूदगी में बीजद में शामिल हुईं। उन्होंने कहा कि ऐसी पार्टी के लिए पसीना बहाने के बाद बदलाव करना मुश्किल है जिसने मेरी मेहनत को नहीं पहचाना। मुझे स्वीकार करने के लिए मैं बीजद को धन्यवाद देती हूं। मैं मु यमंत्री नवीन पटनायक की विकासात्मक गतिविधियों से प्रेरित हूं। मैं बीजद के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करूंगी।

चूंकिए बीजद ने अभी तक बालासोर लोकसभा सीट से अपने उ मीदवार के नाम की घोषणा नहीं की हैए इसलिए लेखाश्री को वहां से टिकट दिया जा सकता है। बीजद ने 2019 में राज्य की 21 लोकसभा सीटों के लिए सात महिला उ मीदवारों को मैदान में उतारा था। हालांकिए इस बार पार्टी ने अब तक केवल छह महिला उ मीदवारों को उ मीदवार बनाया है।

बीजेडी ने जारी की विधानसभा उमीदवारों की तीसरी लिस्ट

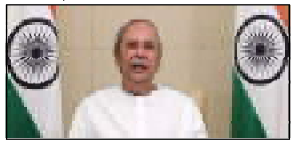

भुवनेश्वर ०९/०४ (संवाददाता): बीजद ने आज अपने विधायकों की तीसरी सूची में नौ उ मीदवारों के नामों की घोषणा की। इसमें पार्टी ने तीन विधायकों को फिर से चुनाव मैदान में उतारा है।इस सूची में एक महिला उ मीदवार का नाम भी शामिल है। पार्टी ने अब तक कुल 147 सीटों में से 108 सीटों के लिए उ मीदवारों की घोषणा कर दी हैए जिसमें आज के उ मीदवार भी शामिल हैं। पार्टी ने जिन विधायकों को फिर से टिकट दिया हैएउनमें सालेपुर से प्रशांत बेहराए राउरकेला से शारदा प्रसाद नायक और बालेश्वर से स्वरूप दास शामिल हैं। रेंगाली से सुदर्शन हरिपालए बीरमित्रपुर से रोहित जोसेफ तिर्कीए केंदुझर से मीना माझीए रायरंगपुर से रायसिन मुर्मु और जयदेव से नवकिशोर मलिक को पार्टी ने नए चेहरे के रूप में टिकट दिया है। बारबाटी.कटक सीट से भाजपा से बीजद में शामिल हुए प्रकाश बेहरा को मैदान में उतारा गया है।पार्टी ने राजगांगपुर से हाल ही में कांग्रेस से आए जॉर्ज तिर्की के बेटे रोहित जोसेफको भी अपना उ मीदवार बनाया है। जयदेव विधानसभा क्षेत्र में गुटबाजी से बचने के लिए पार्टी ने चंदन पात्र समर्थित नवकिशोर मलिक को टिकट दिया है। वहां नवीन निवास का कर्मचारी अक्षय बेहरा टिकट के दावेदार थे।

आरएसपी की सेल हॉकी अकादमी हॉकी इंडिया प्रेसिडेंट अवार्ड 2023 से अलंकृत

राउरकेला ०९/०४ (संवाददाता): राउरकेला इस्पात संयंत्र ;आरएसपी की सेल हॉकी अकादमी को नई दिल्ली में आयोजित एक शानदार समारोह में कई सेलिब्रिटी खिलाड़ियों, कोचों और विभिन्न अकादमियाँ के अधिकारियों की उपस्थिति में हॉकी इंडिया द्वारा ष्हॉकी इंडिया प्रेसिडेंट अवार्ड 2023 से स मानित किया गया।

सेल हॉकी अकादमी की ओर से उप प्रबंधक ;क्रीड़ा श्री रघु नंदन पाढ़ी ने पुरस्कार प्राप्त किया जिसमें एक ट्रॉफीए प्रमाण पत्र और 5 लाख रुपये का नकद पुरस्कार शामिल था। निदेशक प्रभारी कार्यालय के मंथन स मेकलन कक्ष में 3 अप्रैल को आयोजित एक समारोह में मु यक महा प्रबंधक ;नगर प्रशासन एवं सीएसआर श्री पीण्के स्वाईं, महा प्रबंधक ;पीएचए क्रीडा, एसडब्ल्यू एवं हवाई अड्डा श्री राकेश वर्मा और श्री रघुनंदन पाढ़ी ने आरएसपी सह अतिरिक्तर प्रभार बोकारो स्टीनल प्लांवट के निदेशक प्रभारी श्री अतनु भौमिक को पुरस्कार और चेक सौंपे। इस अवसर पर कार्यपालक निदेशक ;वर्क्स श्री एसण्आर सूर्यवंशी, कार्यपालक निदेशक ;कार्मिक एवं प्रशासन सह अतिरिक्त प्रभार परियोजना श्री तरूण मिश्र, कार्यपालक निदेशक ;खान श्री आलोक वर्मा, कार्यपालक निदेशक ;वित्ता एवं लेखा श्री एण्के बेहुरियाए मु यह महा प्रबंधक ;सामग्री प्रबंधन श्री अनिल कुमार और आरएसपी के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।

उल्लेवखनीय है किए आरएसपीकी सेल हॉकी अकादमी ने बीरेंद्र लकड़ा, शिलानंद लकड़ा, पंकज रजाकए राजेश लकड़ा, पावल लकड़ा, जेरोम लकड़ा, सुशील खालखो, आनंद लकड़ा, सुबोध तिर्की, सूरज कांत सिंह, के सुमेश कांत और अन्य जैसे अंतरराष्ट्रीय याति प्राप्त खिलाड़ियों को तैयार करके न केवल राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय हॉकी जगत में अपनी एक अलग पहचान बनाई है।

जमानत के बावजूद जेल से 33 कैदी नहीं हुए रिहा, हाई कोर्ट ने राज्य कानून सेवा प्राधिकरण को दिया ये निर्देश

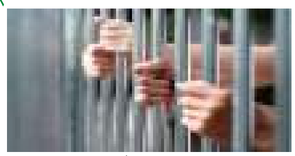

कटक ०९/०४ (संवाददाता): अदालत द्वारा जमानत दिए जाने के बाद भी 33 कैदियों को जेल से रिहा नहीं किया जा सका।हाईकोर्ट में जेल सुधार से जुड़े मामलों की सुनवाई के दौरान ये तथ्य सामने आए। संबंधित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा विभिन्न जेलों का दौरा करने के बाद सौंपी गई रिपोर्ट के अनुसार कुल 155 विचाराधीन कैदियों को पिछले साल दिसंबर तक जमानत दी गई लेकिन उन्हें जेल से रिहा नहीं किया जा सका।155 में से 122 कैदियों को बाद में जमानत पर रिहा कर दिया गया। हालांकिए अन्य 33 कैदी जमानत मिलने के बाद भी जेल में हैं। राज्य कानून सेवा प्राधिकरण ने उच्च न्यायालय को सूचित किया कि जमानत और अन्य कारणों से निर्धारित शर्तों को पूरा न करने के कारण जमानत मिलने के बावजूद कैदियों को जेल से रिहा नहीं किया जा सका है।

उच्च न्यायालय ने इस मुद्दे को गंभीरता से लिया और राज्य कानून सेवा प्राधिकरण को एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। जानकारी के मुताबिक हाईकोर्ट ने कोर्ट से पूछा है कि अब तक जमानत मिलने के बावजूद कितने विचाराधीन कैदी जेल से रिहा नहीं हो पाए हैं और इसके पीछे क्या कारण हैं।उच्च न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया कि जमानत मिलने के बाद भी रिपोर्ट में जेल में बंद कैदियों के नाम और अन्य विवरणों का उल्लेख किया जाए। मु य न्यायाधीश चक्रधारी शरण सिंह और न्यायमूर्ति शिवशंकर मिश्रा की खंडपीठ ने कृष्ण प्रसाद साहू की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया।मामले की अगली सुनवाई 12 अप्रैल को होगी। मामले की सुनवाई के दौरान एमिकस क्यूरी ने जेलों में कैदियों की निर्धारित सं या से अधिक होने के मुद्दे पर उच्च न्यायालय का ध्यान आकर्षित किया।जमानत मिलने के बाद भी जेल में बंद कैदियों की रिहाई के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले और इस संबंध में एसओपी संबंधित तथ्य भी पेश की। एमिकस क्यूरी गौतम मिश्रा मामले को संभाल रहे हैं।

बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम का सफल परीक्षण

बालेश्वर ०९/०४ (संवाददाता): सामरिक बल कमान ;एसएफसीद्ध ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ;डीआरडीओद्ध के साथ मिलकर बुधवार की शाम लगभग सात बजे ओडिशा समुद्र तट पर डॉण् एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से नई पीढ़ी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि.प्राइम का परीक्षण किया। यह अग्नि.1 मिसाइल का स्थान लेगी।

अग्नि सीरीज की मिसाइल में से यह बेहद घातक आधुनिक और मीडियम रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल है। इस मिसाइल को भारतीय स्ट्रैटेजिक फोर्स कमांड के तहत संचालित किया जाएगा। इसे अग्नि पी नाम से भी जाना जाता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह व डीआरडीओ के अध्यक्ष समीर बी कामत ने इस सफल परीक्षण के लिए डीआरडीओए एसएफसी और सशस्त्र बलों को बधाई दी है।इस मौके पर चीफ आफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहानए स्ट्रैटजिक फोर्सेज कमांड के प्रमुखए डीआरडीओ और भारतीय सेना के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। डीआरडीओ के सूत्रों के मुताबिक बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि.प्राइम 2000 किलोमीटर तक प्रहार करने में सक्षम है।

यह मिसाइल 3000 किलोग्राम वजन तक उच्च तीव्रता वाले विस्फोटक परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। यह दो स्टेज के रॉकेट मोटर पर चलने वाली मिसाइल है। इस मिसाइल का वजन 11 हजार किलोग्राम है। यह सालिड यूल से उड़ने वाली मिसाइल है। अग्नि प्राइम मिसाइल हल्के मटेरियल से बनाई गई है।

सामुदायिक शौचालय में ताला

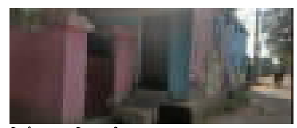

राजगांगपुर ०९/०४ (संवाददाता): स्वच्छ भारत मिशन के तहत नगरपालिका द्वारा लाखों रुपये खर्च कर बनाए गए सार्वजनिक शौचालय का दो महीने से ताला नहीं खोला गया है। ऐसे में राहगीरों सहित बगल में स्थित साप्ताहिक बाजार में सब्जी बेचने और खरीदने आए लोगों को भी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। नगरवासियों की माने तो सामुदायिक शौचालय मात्र दिखावा बन कर रह गया है। स्थानीय लोगों को यह मालूम नही है कि शौचालय आखिर दो महीनों से बंद क्यों है। स्वच्छता अभियान पर जोर देते हुए नगर को खुले में शौच मुक्त करने के लिए सार्वजनिक सामुदायिक शौचालयों का निर्माण नगरपालिका की तरफ से कराया गया है लेकिन इसका उपयोग दो महीने से नहीं हो रहा है।

जन सुविधा के लिए बना सामुदायिक शौचालय बंद रहता है। वार्ड नंबर एक में ठीक नगरपालिका के सामने बने इस सामुदायिक शौचालय के आसपास रहने वाले लगभग तीन दर्जन परिवारों के पास अपना शौचालय नहीं है। सामुदायिक शौचालय का निर्माण होने से लोगों में आस जगी थी कि अब खुले में शौच से मुक्ति मिल जाएगीए पर ऐसा नहीं हुआ। लोगों ने बताया कि दो महीने से यह शौचालय बंद पड़ा हुआ है। लोगों का कहना है कि सरकार द्वारा लाखों रुपये खर्च करने के बाद भी योजना के लाभ से गरीब वंचित हैं। अगर सामुदायिक शौचालय नियमित खुले तो लोग उसी में शौच के लिए जाएंगे। स्थानीय निवासियों ने सामुदायिक शौचालय में दो महीने से लगा ताला जल्द खुलवाने की मांग नगरपालिका के अधिकारियों से की है। कहा है कि इस ओर ध्यान दिया जाए।

कटक में फिर से पैर पसार रहा पीलिया, 40 से अधिक लोग आए चपेट में

कटक ०९/०४ (संवाददाता): प्राचीन नगरी कटक में फिर से पीलिया का प्रकोप देखने को मिला है। कटक शहर के 52 नंबर वॉर्ड में पीलिया के चपेट में आकर 40 से अधिक लोग इलाज करवा रहे हैं। इसमें से चार से पांच लोगों की हालत गंभीर होने के कारण उन्हें इलाज के लिए अस्पताल लिया गया है।

मिली जानकारी के अनुसारए कटक नगर निगम के 52 नंबर वॉर्ड राजेंद्र नगर इलाके में पीलिया फैलने की खबर सामने आई है। यहां के लोग पिछले कुछ दिनों से पीलिया के चपेट में एक के बाद एक आने लगे और यह आंकड़ा इस बीच 40 के ऊपर पहुंच चुकी है।

इसके बारे में खबर पाकर कटक नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया है। स्थानीय लोगों के आरोप के अनुसारए यहां पर पानी काफी प्रदूषित है और पेयजल पाइप की हालत भी खराब है। कई जगहों पर पेय जल पाइप नालियों से होकर गया हुआ है और इसके चलते पानी पाइप का जल दूषित होने के कारण लोग पीलिया से संक्रमित हो रहे हैं।

उस इलाके की सफाई और खास तौर पर वहां पर मौजूद पाइप लाइन की सफाई के ऊपर कटक नगर निगम अब काफी अहमियत दी है। जल्द से जल्द वहां पर मौजूद पाइपलाइन की खुदाई कर उसकी सफाई करना है। इसके साथ ही साथ वहां पर देखे जाने वाली पेयजल की समस्या को दूर करने के लिए सीएमसी की ओर से निर्णय लिया गया है।

कटक नगर निगम की टीम उस इलाकों का दौरा करते हुए घर से घर तक घूम कर हलोजेन टैबलेट और अन्य दवाई लोगों को प्रदान कर रही है। आगे आवश्यकता के अनुसार ठोस कदम उठाए जाने के बारे में सीएमसी की ओर से गण माध्यम को जानकारी दी गई है।

आरएसपी द्वारा वित्त वर्ष 2023–24 में प्रमुख क्षेत्रों में स्थापना के बाद से अब तक का सर्वश्रेष्ठं उत्पादन रिकॉर्ड दर्ज

राउरकेला ०९/०४ (संवाददाता): राउरकेला इस्पात संयंत्र ;आरएसपी ने वित्तीय वर्ष 2023–24 को प्रमुख उत्पादन क्षेत्रों में स्थापना के बाद से अब तक सर्वश्रेष्ठर उत्पादन रिकॉर्ड के साथ समाप्त किया। आरएसपी ने वित्त वर्ष 2023–24 में 4494258 टन हॉट मेटलए 4161241 टन क्रूड स्टील और 4211205 टन विक्रेय योग्य स्टील का उत्पादन किया और स्थापना के बाद से अब तक का अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दर्ज कर साल.दर.साल क्रमश: 4.3 प्रतिशत, 3 प्रतिशत और 11.6 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की।

विशेषत: इस्पात संयंत्र ने पिछले वित्तीय वर्ष में अपने इतिहास में पहली बार 4 मिलियन टन विक्रेय योग्य इस्पात उत्पादन का आँकड़ा पार किया। ब्लास्ट फर्नेस.5 ;बीएफ-5 से हॉट मेटल का उत्पादन 2876540 टन के सर्वकालिक उच्च स्तर को छू गयाए जबकि स्टील मेल्टिंग शॉप ने किसी भी वित्तीय वर्ष की अपेक्षा अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दर्ज करने के लिए 3661172 टन क्रूड स्टील का उत्पादन किया। सिंटर संयंत्रों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए 7160788 टन सिंटर का उत्पादन किया और किसी भी वित्तीय वर्ष के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दर्ज किया। हॉट स्ट्रिप मिल. 2 ;एचएसएम.2 की सफलता में एक और प्रमुख सहयोगी था जिसने 2375457 टन एचआर कॉइल्स की अब तक की उच्चतम क्षमता हासिल की और इस तरह पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 34 प्रतिशत की भारी वृद्धि दर्ज की । यह प्रवृत्ति प्रेषण में भी परिलक्षित हुई और इस्पात संयंत्र ने 2023–24 में 4152343 टन सेलेबल स्टील का सर्वकालिक सर्वश्रेष्ठ रिकॉर्ड प्रेषण किया जो 2022–23 के अपने पहले के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के अपेक्षा काफी बेहतरीन रहा । तकनीकी. आर्थिक क्षेत्र मेंए इस्पात संयंत्र ने 2023–24 में सर्वश्रेष्ठ वार्षिक प्रदर्शन दर्ज किया। विशिष्ट ऊर्जा खपत 5॰98 गीगाकैलोरीध्टन कच्चे स्टील की थीए जबकि विशिष्ट बिजली खपत 446.2 किलोवाट प्रति टन विक्रेय योग्य स्टील थी और विशिष्ट पानी की खपत 3.02 क्यूबिक मीटर प्रति टन क्रुड स्टील थी। सीपीपी–1 और सीपीपी–3 पर संयुक्त विद्युत उत्पादन भी पिछले वित्तीय वर्ष में 69.17 मेगा वाट के साथ सर्वकालिक सर्वश्रेष्ठ था।पिछले वित्तीय वर्ष में आरएसपी का शानदार प्रदर्शन व्यक्तिगत विभागों द्वारा कई राष्ट्रीय रिकॉर्डों से भरा हुआ था। राष्ट्रीय रिकॉर्ड में मार्चए 2024 में हासिल की गई 2865 हीट की टॉरपीडो लैडल अभियान अवधि और जनवरीए 2024 में हासिल की गई 309 हीट में से कास्टर.3 में अब तक का सबसे लंबा अनुक्रम शामिल है।

आरएसपी सह अतिरिक्तं प्रभार बोकारो स्टीहल प्लांट के निदेशक प्रभारीए श्री अतनु भौमिक ने शानदार प्रदर्शन के लिए टीम को बधाई देते हुए कहा ष्आने वाले दिन अधिक चुनौतीपूर्ण हैं। ध्यान में रखते हुए चालू वित्त वर्ष के लिए हमने जो कड़े लक्ष्यों स्वीकार किये है उन्हें प्राप्त करने के लिए हमें अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान देने की आवश्यकता है।

Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at: http://www.software602.com/
kalinga pg-6 for 10-APR.pmd 1 4/10/2024, 2:04 PM